● वर्ष-3
● अंक-262
रायपुर, बुधवार
12 जून 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ ...

केंद्र ने फिर भेजी छग को 4,761 करोड़ की राशि

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी का छत्तीसगढ़ से अटूट नाता

छत्तीसगढ़ को अब तक श्री मोदी ने दिए लगभग 4 लाख करोड़

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को वर्ष 2024-2025 से संबधित 4761.30 करोड़ रुपए की संपूर्ण राशि हस्तांतरित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से आभार व्यक्त किया है। देव ने कहा कि केंद्र से प्राप्त यह राशि छत्तीसगढ़ के विकास और जनकल्याण के भाजपा के संकल्प की पूर्ति के प्रयासों को गति प्रदान करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदैव छत्तीसगढ़ के प्रति अपने आत्मीय जुड़ाव का परिचय देते रहे हैं। इससे पहले मोदी ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ को केंद्र की ओर से प्रदान की है। श्री देव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार तेजी के साथ अपने संकल्पों और मोदी की गारंटी पर काम करके अभूतपूर्व जन विश्वास अर्जित किया है। जनता का अब केवल भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्त्व पर अटूट विश्वास का रिश्ता जो कायम हुआ है, वह छत्तीसगढ़ को नित नई ऊँचाइयों पर लेकर जाएगा। देव ने इस बात पर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ को लगातार महत्व दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार के सहयोग से न केवल विकास की गति तेज होगी, अपितु हर स्तर पर सुशासन की स्थापना होगी।

सच्चा सेवक अहंकार नहीं दिखाता: मोहन भागवत

नागपुर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक सच्चा सेवक (जो लोगों की सेवा करता है) कभी अहंकार नहीं दिखाता और सार्वजनिक जीवन में हमेशा मर्यादा बनाए रखता है। इंडियन एक्सप्रेस ने संघ प्रमुख के हवाले से कहा कि एक सच्चा सेवक काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है। जो मर्यादा रखता है वह अपना काम करता है, लेकिन अनासक्त रहता है। इसमें कोई अहंकार नहीं है कि मैंने ये किया. केवल ऐसे व्यक्ति को ही सेवक कहलाने का अधिकार है।

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में हिंसा प्रभावित मणिपुर का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य एक साल से अधिक समय से शांति का इंतजार कर रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि मणिपुर अब एक साल से शांति की तलाश में है। इस पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए. पिछले 10 वर्षों से राज्य शांतिपूर्ण था। ऐसा लगा जैसे पुरानी बंदूक संस्कृति ख़त्म हो गई हो। वहां अचानक जो तनाव बढ़ गया या फिर भड़का दिया गया, उसकी आग में वह अब भी जल रहा है. उस पर कौन ध्यान देगा? इसे प्राथमिकता देना और इस पर ध्यान देना कर्तव्य है।

उनकी यह टिप्पणी नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के एक दिन बाद आई है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा देखी जा रही है। मोहन भागवत ने कहा कि चुनावी राजनीति एक प्रतियोगिता है, युद्ध नहीं।

चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसमें दो दल होते हैं इसलिए प्रतिस्पर्धा होती है। एक को आगे बढ़ाने और दूसरे को पीछे धकेलने का काम होता है। इसका उपयोग न करें, लोग निर्वाचित क्यों हो रहे हैं? वे संसद में जाकर बैठेंगे और देश को चलाएंगे, सर्वसम्मति बनाकर चलाएंगे, हमारी परंपरा सर्वसम्मति बनाकर चलाने की है।

मणिपुर के बारे में मोदी को भी ''ज्ञान'' दें भागवत: दिग्विजय

इंदौर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मणिपुर के हालात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर मंगलवार को निशाना साधते हुए कहा कि भागवत को इस बारे में मोदी को भी समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत द्वारा मणिपुर के बारे में मोदी को भी ''ज्ञान'' दिया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में जातीय हिंसा की शुरुआत के बाद से अब तक प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया है। भागवत ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मणिपुर पिछले एक साल से शांति की राह देख रहा है और इस संघर्षग्रस्त राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार किया जाना चाहिए।

संघ प्रमुख के इस बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए दिग्विजय सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, मैं भागवत से अनुरोध करूंगा कि वह यह ज्ञान प्रधानमंत्री मोदी को भी दें। वह (मोदी) अब तक वहां (मणिपुर) गए नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनके नाम के आगे से मोदी का परिवार शब्द हटा लें। इस बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा, मोदी का परिवार तो बन चुका है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, वे सब मोदी के परिवार के अंग बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने (मोदी समर्थकों ने) शायद शर्म के कारण अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार शब्द हटाया होगा। इस सिलसिले में संभवत: संघ परिवार ने भी कोई आदेश दिया होगा।

नई दिल्ली। एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इससे बहुत ताकत मिली है. चुनाव अभियान के दौरान, पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है समय, एक तरह का रिकॉर्ड है, और इसने हमें अपने राष्ट्र की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है।

भाजपा नेताओं के नाम में अब नहीं दिखेगा 'मोदी का परिवार' मोदी की खास अपील, बोले-

हमारा बंधन अटूट

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूरे भारत में लोगों से अनुरोध किया कि वे अब अपने सोशल मीडिया हैंडल से मोदी का परिवार (मोदी का परिवार) हटा दें, यह कहते हुए कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की चुनावी जीत ने प्रभावी ढंग से वह संदेश दे दिया है जो वह देना चाहती थी। इस साल मार्च में कई भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों ने राजद प्रमुख लालू यादव द्वारा अपना कोई परिवार न होने के लिए कहे जाने के बाद पीएम मोदी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया बायो में मोदी का परिवार जोड़ा था। प्रधान मंत्री ने जवाब दिया था कि भारत के लोग उनका परिवार हैं।

एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इससे बहुत ताकत मिली है. चुनाव अभियान के दौरान, पूरे भारत में लोगों ने मेरे प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार जोड़ा। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है समय, एक तरह का रिकॉर्ड है, और इसने हमें अपने राष्ट्र की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। मोदी ने कहा कि हम सभी के एक परिवार होने का संदेश प्रभावी ढंग से दिए जाने के बाद, मैं एक बार फिर भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि अब आप अपनी सोशल मीडिया संपत्तियों से मोदी का परिवार हटा दें।

नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए, सुप्रिया सुले बोलीं-

पूरी तरह ये केंद्र सरकार की नाकामी

मुंबई। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जिस तरह से यह नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे ख्याल से एसआईटी की जांच का जो आदेश आया है वह जल्द से जल्द होना चाहिए। बच्चों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसके बारे में शिक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए। यह पूरी नाकामी केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया है वह सब पाक साफ है। शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। पीठ ने हालांकि सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केंद्र और एनटीए के अलावा पीठ ने बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया। राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। पीठ ने कहा, आपको कितना समय चाहिए?

भाई-भतीजावाद को लेकर राहुल का मोदी पर हमला, बोले-

'सरकारी परिवार' को बांट रहे सत्ता की वसीयत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा पर परिवारवाद की राजनीति की बात आने पर पाखंड का आरोप लगाया। राहुल ने आरोप लगाया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई मौकों पर कांग्रेस नेताओं के बलिदान को भाई-भतीजावाद कहकर खारिज कर दिया है, वहीं सोमवार को पोर्टफोलियो आवंटन में एक सरकारी परिवार को सत्ता का वितरण देखा गया। कांग्रेस सांसद ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, जो लोग पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को भाई-भतीजावाद कहते हैं, वे सत्ता की इच्छा को अपने सरकारी परिवार को बांट रहे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि पीढ़ियों के संघर्ष, सेवा और बलिदान की परंपरा को परिवारवाद कहने वाले अपने 'सरकारी परिवार' को सत्ता की वसीयत बांट रहे। कथनी और करनी के इसी फर्क को नरेंद्र मोदी कहते हैं! पोस्ट के साथ राहुल ने 20 कैबिनेट मंत्रियों की सूची भी साझा की, जिनके रिश्तेदार पहले केंद्र या राज्य सरकारों में पदों पर थे।

राहुल गांधी द्वारा साझा की गई सूची है- एचडी कुमारस्वामी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे, जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते, रामनाथ ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र, राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र, रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते, ज्वोतिरादित्व सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया के पुत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, राम मोहन नायडू, येरेन नायडू के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल के बेटे, किरण रिजिजू, रिनचिन खारू के पुत्र, पहले प्रो-टर्म स्पीकर, अरुणाचल, जेपी नड्डा, दामाद, जयश्री बनर्जी, पूर्व सांसद एवं मंत्री, मध्य प्रदेश, जितिन प्रसाद, पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश, जितेंद्र प्रसाद के पुत्र, कीर्ति वर्धन सिंह, महाराज आनंद सिंह के पुत्र, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री देबेंद्र प्रधान के पुत्र, अनुप्रिया पटेल, संस्थापक-बहुजन समाज पार्टी और अपना दल, सोनेलाल पटेल की बेटी, रक्षा खडसे, एकनाथ खडसे की बहू,

प्रमुख समाचार

ले. जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख

नई दिल्ली। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून की दोपहर से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे 30 जून को कार्यालय छोड़ रहे हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम) और अति विशिष्ट सेवा मेडल (एवीएसएम) से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में सेवाएं दी हैं। सरकार ने 25 मई को छठवें चरण के चुनाव के बाद 26 मई को थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को एक महीने का सेवा विस्तार दिया था। इस वजह से वह 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे 31 मई को रिटायर होने वाले थे। रक्षा मंत्रालय का कहना था कि आर्मी रूल्स, 1954 के नियम 16 ए (4) के तहत ये सेवा विस्तार दिया गया था। 1 जुलाई, 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 दिसंबर, 1984 को भारतीय सेना की इन्फैंट्री (जम्मू और कश्मीर राइफल्स) में कमीशन दिया गया था। करीब 40 वर्षों की अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम किया है। लेफ्टिनेंट द्विवेदी की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट (18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स), ब्रिगेड (26 सेक्टर असम राइफल्स), डीआईजी, असम राइफल्स (पूर्व) और 9 कोर की कमान शामिल है।

मोहन चरण माझी होंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री

ओड़िशा। मोहन माझी ओडिशा के पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यमंत्री होंगे। बीजू जनता दल (बीजेडी) प्रमुख नवीन पटनायक का 24 साल पुराना कार्यकाल राज्य विधानसभा चुनावों में भारी हार के बाद समाप्त हो गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री का चयन भाजपा विधायक दल की बैठक में किया गया, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेन्द्र यादव शामिल हुए। कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा उप मुख्यमंत्री होंगे। विशेष रूप से, भाजपा ने 2000 और 2004 में बीजद के गठबंधन सहयोगी के रूप में राज्य पर शासन किया था और यह पहली बार है कि पार्टी ओडिशा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। मोहन चरण माझी ने क्योंझर सीट लगभग 87,815 वोटों के अंतर से जीती। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से बीजद की मीना माझी को हराया। ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के कारण 12 जून को दोपहर 1 बजे के बाद भुवनेश्वर में सभी राज्य सरकार के कार्यालय और अदालतें बंद हो जाएंगी।

इंडिया ब्लाक के 6 सांसदों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसमें विपक्ष को अंतत: सत्तारूढ़ गठबंधन की तुलना में राज्य में अधिक सीटें मिलीं। हालाँकि, राज्य में आम चुनाव परिणाम ख़तरे में पड़ सकते हैं क्योंकि इंडिया ब्लॉक के छह सांसद कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें दो साल से अधिक की जेल हो सकती है। यदि इंडिया ब्लॉक के छह सांसदों को उनके चल रहे आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो वे अपनी संसदीय सदस्यता खो देंगे। उनमें से सबसे उल्लेखनीय हैं ग़ाज़ीपुर के सांसद अफ़ज़ल अंसारी, जो गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, जिनकी इस साल की शुरुआत में मृत्यु हो गई थी। अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में पहले ही चार साल की सजा सुनाई जा चुकी है। उनकी दोषसिद्धि पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, जिससे उन्हें आम चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। हालांकि, मामले की सुनवाई जुलाई में होगी जब अदालत फिर से खुलेगी। यदि अदालत उनकी सजा बरकरार रखती है तो वह अपनी संसद सदस्यता खो देंगे।

सतनामी समाज के प्रमुखों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा है कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़े। सतनामी समाज प्रमुखों ने कहा कि समाज के सभी लोग घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, वे असामाजिक तत्व थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे। शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए हम सब दृढ़संकल्पित है। गौरतलब है कि सतनामी समाज के राज्यभर से आए प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री श्री साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और बलौदाबाजार जिले में हुई घटना के संबंध में शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की।

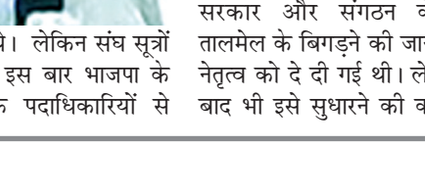

कठुआ में आतंकियों ने की फायरिंग, एक दहशतगर्द ढेर

जम्मू। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के हीरानगर इलाके के सैडा सोहल गांव में मंगलवार की रात मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। आतंकियों ने एक घर में घुसकर परिवार वालों को बंधक बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर फायरिंग की। इसके बाद किसी तरह से परिवार वालों ने घर से निकलकर सुरक्षा बलों को सूचना दी। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। ऑपरेशन जारी है।बताते हैं कि यह गांव कठुआ व सांबा जिले के बॉर्डर पर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस गांव में शाम को लगभग पौने आठ बजे ग्रामीणों ने संदिग्ध लोगों की हरकत देखी। इस दौरान दो आतंकी एक घर में घुस गए और खाना मांगने लगे। परिवार वालों ने उनके पास के सामान को लेकर आपत्ति जताई तो धमकी देते हुए दो तीन चक्र गोलियां चलाईं। इस पर परिवार वाले चुप हो गए। किसी तरह वह खाने का बंदोबस्त करने की बात कहते हुए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाद में उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना दी। सूचना मिलते ही कठुआ, सांबा व जम्मू से सुरक्षा बलों की टीमें ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू कर दी।

सतह पर आया भाजपा-आरएसएस का तनाव! शीर्ष नेताओं पर उठ रहे सवाल

अमित शर्मा

लोकसभा चुनाव बीतने के बाद भाजपा और आरएसएस का तनाव सतह पर आ गया है। मणिपुर में हो रही हिंसा को शांत करने में असफलता और चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा उपयोग की गई अभद्र भाषा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान इसी तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों संगठनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसके ठीक बाद संघ का मुखपत्र मानी जाने वाली एक पत्रिका में छपे एक लेख ने इस तनाव पर पड़े सभी पर्दे हटा दिए हैं। लेख में आरोप लगाया गया है कि चुनावों के दौरान भाजपा नेता-कार्यकर्ता आरएसएस नेताओं-कार्यकर्ताओं से सहयोग लेने के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई है।

दरअसल, काफी लंबे समय से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि दोनों संगठनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसका सबसे पहला संकेत तब मिला था जब आरएसएस ने अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। संगठन लगभग दो साल से इस बात की योजना बना रहा था कि संघ की स्थापना के सौ साल पूरे होने पर 2025 में पूरे देश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए संघ को देश के सभी गांवों तक ले जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही थी।

लेकिन अचानक ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अप्रैल में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा कर दी थी कि संघ अपने जन्मशती के कार्यक्रम को भव्य तरीके से नहीं मनाएगा। उन्होंने कहा कि संघ बेहद सादगीपूर्ण तरीके से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करता है, संघ के स्वयंसेवक यह काम करते रहेंगे। लेकिन संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर कोई भव्य कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जाएंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन तनावों को कभी सतह पर नहीं आने दिया। लेकिन उनके एक बयान की काफी चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि भाजपा अब काफी परिपक्व हो चुकी है और उसे अब आरएसएस के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नड्डा का यह बयान बेहद संतुलित संदर्भों में था, लेकिन इसका आशय यही निकाला गया कि भाजपा-आरएसएस में तनाव ज्यादा है। पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा।

बैठकें हुईं, लेकिन कार्य नहीं हुआ- लोकसभा चुनावों के पहले संघ के बेहद वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चुनावों को लेकर पार्टी के साथ समन्वय करने की कोशिश की थी। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण कुमार ने चुनावों की घोषणा से पूर्व ही गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में लगातार पांच दिन तक मैराथन बैठकें की थीं। कहा गया था कि संगठन के शीर्ष नेता देश की एक-एक सीट का गंभीर आकलन कर हर लोकसभा चुनाव के अनुसार अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य चुनाव में 400 सीटों के असंभव से लक्ष्य को हासिल करना बताया गया था। इसी तरह की बैठकें राज्यों के स्तर पर भी किए गए थे। लेकिन संघ सूत्रों का कहना है कि इस बार भाजपा के कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों से अपेक्षित सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। कई सीटों पर भाजपा नेताओं को सब कुछ ठीक न होने की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन इस पर समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया। उलटे जिन उम्मीदवारों के बारे में संघ से नकारात्मक संकेत दिए गए थे, उन्हें भी टिकट पकड़ा दिया गया। पार्टी को इसका चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा।

यूपी के संकेतों को भी किया नजरअंदाज- संघ सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनावों के पूर्व ही भाजपा नेतृत्व को यूपी में संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक न होने की जानकारी दे दी गई थी। चुनाव के बीच भी सरकार और संगठन के आपसी तालमेल के बिगड़ने की जानकारी पार्टी नेतृत्व को दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी इसे सुधारने की कोशिश नहीं की गई। उलटे भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं के बयानों ने स्थिति को और ज्यादा उलझाने का ही काम किया।

नाजुक दौर में संबंध सुधारना बेहद महत्त्वपूर्ण - केंद्र में भाजपा की सरकार अब सहयोगी दलों के सहारे है। उसे एनडीए के विभिन्न सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ रहा है। इससे उसकी निर्भरता बढ़ गई है। इस साल में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अगले वर्ष दिल्ली-बिहार के चुनावों में भाजपा नेतृत्व की परीक्षा होनी है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ कम से कम चार-पांच राज्यों में अध्यक्षों का बदलाव भी होना है। यदि ऐसे समय में दोनों संगठनों में आपसी तालमेल बेहतर नहीं रहता है तो भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बलौदाबाजार हिंसा के उपद्रवियों संगठनों की हुई पहचान, प्रशासन ने जारी किए नाम

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में सोमवार की शाम को हुई घटना के बाद आज वहां स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अफसर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां आज स्थिति का जायजा लिया वहीं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। इस पूरी घटना में उपद्रवियों को चिन्हाकित किए जाने की भी जानकारी प्रशासन के पास है और आने वाले समय में कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस हिंसा में घायलों का इलाज अस्पतालों में जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेहतर इलाज करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं जिसके बाद अफसरों ने घायलों का अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और उनके बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए।

उल्लेखनीय हैं कि गिरौदपुरी के महकोनी गांव में संत अमरदास की तपोभूमि के जैतखाम को काटे जाने के बाद सतनामी समाज अंदर ही अंदर उद्देलित था और सोमवार को एकाएक उग्र हो उठा जिसके चलते आंदोलनकारियों ने शासकीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और वहां खड़े वाहनों में भी तोडफ़ोड़ की। हालांकि उस समय वहां पर जो पुलिस बल मौजूद था वह इस उग्र भीड़ को नियंत्रित

करने में नाकाम रहा जिसके चलते यह वाक्या हुआ। इस पूरी घटना में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं वहीं प्रदर्शनकारियों ने कारों और दुपहिया वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। सतनामी समाज के लोगों द्वारा किए गए उग्र प्रदर्शन के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है।

प्रशासन ने इस हिंसा को अंजाम देने वाले संगठनों को चिन्हांकित कर लिया है और उनके नाम भी जारी किए गए हैं जिनमें आयोजनकर्ता किशोर नवरंगे भीम कांतीवीर अध्यक्ष, दीपक घृतलहरे प्रगतिशील सतनामी समाज, मोहन बंजारे प्रगतिशील सतनामी समाज युवा प्रदेश अध्यक्ष, सुशील बंजारे प्रगतिशील सतनामी समाज युवा प्रकोष्ट, जितेन्द्र नौरंगे सतनाम सेवा समिती जिला अध्यक्ष, ओमप्रकाश खुंटे सतनामी समाज वरिष्ठ, भुनेश्वर डहरिया, दिनेश चतुर्वेदी भीम रेजिमेंट प्रदेश अध्यक्ष आदि शामिल है, जिनके नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन के रूप में आस पास पैदल रैली कर संयुक्त जिला कार्यालय का घेराव किये जाने योजना थी, जिसमें शासन द्वारा उच्चस्तरीय न्यायिक जांच का आश्वासन दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं किया और जिसके फलस्वरुप आंदोलन उग्र हो गया और उसने सरकारी संपत्ति तथा वाहनों को अपना निशाना बनाया। जिसके कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, नुकसान के आंकलन के बाद जिसकी भरपाई भी इन्हीं आंदोलनकारियों से किए जाने की जानकारी है। इनके साथ ही अब तक इस मामले में पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि, 10 जून को छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा अमर गुफा गिरौधपुरी जैतखाम मामले में उच्चस्तरीय जांच की मांग एवं साथ में पूर्व में बोडसरा, कबीरधाम एवं अन्य जिलों में सतनामी समाज संबंधी विभिन्न मुद्दो को लेकर दशहरा मैदान बलौदाबाजार में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसमें सुरक्षा प्रबंध के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाने के सांथ मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी आदेशित किया गया था।

तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा। गंगालूर, भैरमगढ़ एवं कटेकल्याण एरिया कमेटी सक्रिय तीन नक्सलियों मनकेली/पेद्दाकोरमा पंचायत जनमिलिशिया सदस्य संजय बारसे पिता स्व. बुधराम बारसे निवासी तिमेनार कारमपारा थाना मिरतुर जिला बीजापुर, कुन्ना पंचायत कमेटी सदस्य सुकड़ा मड़कामी पिता स्व. मुक्का मड़कामीर निवासी कुन्ना तराई टिकरापारा थाना कूकानार जिला सुकमा एवं ग्राम फुलगट्टा संघम सदस्या रिना कोरसा पति बुड़ता वेको निवासी फुलगट्टा (हाल पनेड़ा कोलूपारा थाना गीदम) थाना मिरतुर जिला बीजापुर ने डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण कर दिया है। उपरोक्त नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में आसूचना शाखा आरएफटी रेंज दन्तेवाड़ा, डीआरजी दंतेवाड़ा एवं 230वीं वाहिनी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा का विशेष योगदान रहा। जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ सभी भटके हुए माओवादियों से अपील करती है कि हिंसा की धारा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुडऩे के लिए निकटतम थाना अथवा कैंप में सम्पर्क करें और क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे।

पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल

बाजार नीलामी के नाम पर सरपंच और सचिव मिलकर डकार गए रुपये

कवर्धा। कबीरधाम जिले के कुंडा ग्राम पंचायत में बाजार नीलामी के नाम पर 50 लाख रुपये का भ्रष्टाचारी करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने सरपंच और सचिव के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर दंडाधिकारी से शिकायत की और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मामले की जांच कराने की बात कही है और शिकायत सही पाने पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मामले का उजागर होते देख सरपंच ने शिकायतकर्ता शेख रहीम खान को धमकी देने लगा है।

दरअसल, कुंडा ग्राम पंचायत में वर्ष 2020 में हाट बाजार की नीलामी हुई थी ताकि इस पैसे से ग्राम पंचायत का विकास किया जा सके और निवासियों को सर्व सुविधा मिल सके। कुंडा ग्राम पंचायत के लोग आज भी विकास की राह टकटकी लगाए देख रहे हैं लेकिन भ्रष्ट सरपंच और सचिव के कारण कुंडा का विकास नहीं हो पाया है। सरपंच और सचिव के मिली भगत से लगभग चार सालों से हाट बाजार नीलामी के 50 लाख रुपये को पंचायत के खाते में जमा नहीं किया है और पूरे पैसे को सरपंच-सचिव ने मिलकर डकार गए।

शिकायतकर्ता शेख रहीम खान को ग्राम पंचायत कुंडा बाजार नीलामी के पैसे को जमा नहीं करने की भनक लगी थी। उसके बाद शेख रहीम ने ग्राम पंचायत कुंडा में आरटीआई लगाया। जहां सचिव ने 60 पन्नों की अधूरी जानकारी दी थी। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है।

मिली जानकारी के अनुसार, शिकायत होने की जानकारी मिलने के बाद सरपंच ने हाल ही में पंचायत के खाते में 10 लाख रुपये जमा किया है। अभी भी लगभग 40 लाख रुपये जमा करना बाकी है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि अपने कारनामा को छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता शेख रहीम खान ने सरपंच पर धमकी देने का आरोप लगाया है।

19 लोगों की मौत के बाद भी नहीं ले रहे सबक

छोटा हाथी वाहन पलटा छह लोग घायल

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के तहत कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम बाहपानी घाट में बीते माह 20 मई को पिकअप वाहन 30 फीट नीचे खाई में गिर गया था। हादसे में 19 आदिवासियों की मौत और 16 घायल हुए। ये सभी ग्राम सेमरहा के रहने वाले है, जो जंगल से तेंदूपत्ता तोड़कर वापस अपने घर जा रहे थे। इतने बड़े हादसे के बाद अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। लोग वर्तमान में भी पिकअप वाहन में सफर कर रहे हैं।

मंगलवार की सुबह करीब 7.30 बजे ऐसा ही एक हादसा हो गया है। यह हादसा कवर्धा से पोंड़ी नेशनल हाईवे स्थित ग्राम हरिनछपरा के पास हुआ है। हादसे में 6 लोग घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात को पांडातराई में उर्स के मौके पर कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कवर्धा के एक टेंट हाऊस द्वारा टेंट का सामान लगाया गया था।

आज मंगलवार को कार्यक्रम होने के बाद सुबह 7 बजे पांडातराई से छोटा हाथी वाहन में 11 लोग समेत कुर्सी व अन्य सामान भरकर वापस कवर्धा आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम हरिनछपरा में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 6 लोग घायल हुए है। डॉयल 112 व पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया है। सभी घायल को हल्की चोट आई है। इसी तरह सोमवार को भी एक पिकअप वाहन में लोग बैठे हुए थे। इस पर कवर्धा के यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समन शुल्क वसूला है। बाहपानी हादसा के बाद अब तक पूरे जिले में ऐसे लापरवाही पूर्वक वाहन का उपयोग करने वालों से करीब चार लाख रुपए समन शुल्क वसूला गया है।

दो हाथियों को आतंक, ग्रामीणों में भारी गुस्सा

मरवाही में किसानों की फसलों को नुकसान

मरवाही। छत्तीसगढ़ के मरवाही में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। मरवाही वनमंडल में दो हाथियों का समूह लगातार विचरण कर रहा है। विवरण के साथ जंगल से लगे कई गांवों के किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

दरअसल, दो हाथियों का समूह पिछले दिनों मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के मरवाही वन परिक्षेत्र के घुसरिया बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक 2051 में पहुंचे गए और पिछले 25 दिनों से ये दोनों हाथी दिन में तो आराम करते हैं और उसके बाद देर शाम होने पर पहाड़ से उतरकर जंगल से लगे चिचगोहना, कुम्हारी घुसरिया आदि आधा दर्जन से अधिक गांवो के किसानों के खेतों में लगी धान एवं अन्य तरह की फसलों को निरंतर अपना आहार बना रहे हैं।

जिसमें से एक हाथी विगत 25 दिनों से जो एक दांत वाला है और दूसरा हाथी, जो दो दांत वाला है। विगत एक सप्ताह से साथ में दोनों मिलकर विचरण कर रहे हैं। दो हाथियों के निरंतर विचरण से वन परिक्षेत्र मरवाही के ग्रामीण परेशान है, जो रात-रात भर जागरण कर अपने खेतों में लगी फसलों को बचाने का प्रयास करते हैं।

बीती शाम भी ये दोनों हाथी पहाड़ से उतरकर तालाब में पानी पीने, सोननदी में नहाने बाद अंधेरा होते ही घुसरिया गांव के मंजीदटोला से चिचगोहना गांव में धान की फसल खा ली। हाथियों के द्वारा लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने से ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है।

वन विभाग के पास हाथियों से निपटने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। वो सिर्फ हाथियों की निगरानी ही करते हैं और जिस ओर हाथियों के जाने की जानकारी मिलती है। उस ओर पड़ने वाले गावों के ग्रामीणों को मुनादी के जरिये सतर्क रहने की जानकारी देते है।

सरकारी अस्पताल में फर्श पर डिलीवरी बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

■ सीएस, कलेक्टर और सीएमओ समेत कई को नोटिस जारी

बिलासपुर। अंबिकापुर में एक स्वास्थ्य केंद्र में फर्श पर महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया, जिस पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से हलफनामे पर जवाब तलब किया है। मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग संचालक, कलेक्टर सरगुजा के साथ सीएमओ अंबिकापुर, सिविल सर्जन अंबिकापुर और मेडिकल ऑफिसर नवानगर को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, अंबिकापुर के जिला मुख्यालय से लगे नवानगर निवासी प्रियावती पैकरा 9 माह की गर्भवती थी। दरिमा उप स्वास्थ्य केन्द्र में 8 जून 2024 को प्रसव पीड़ा होने पर उक्त महिला मितानिन के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, लेकिन वहां न तो कोई डॉक्टर और न ही कोई नर्स मौजूद थी। परिजन और मितानिन ने कई बार डॉक्टर व नर्स को फोन लगाया पर किसी ने नहीं उठाया। फिर मितानिन ने फर्श पर महिला का असुरक्षित प्रसव कराया।

इस मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा है, कि जब राज्य सरकार राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाली जनता को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रही है तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। स्वास्थ्य केंद्रों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी स्वयं अनुपस्थित हैं जब उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। सुनवाई के बाद डीबी ने सचिव, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, रायपुर को निर्देश दिया है कि, वे घटना के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें और आगे सुनिश्चित करें जो वीडियो इस घटना का ऑनलाइन वायरल किया गया है, उसे आगे प्रसारित करने से भी तत्काल रोका जाए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

महतारी वंदन बना महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का आधार

बलरामपुर। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं है। महतारी वंदन योजना की शुरुआत से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का द्वार खुल गया है, सभी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है। ग्रामीण अंचल की महिलाएं भी अब अपनी आवश्यक जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। योजना से मिलने वाली राशि अब उन महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है जो अकेले अपने परिवार का खर्च चला रही हैं, महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि से उन्हें काफी मदद मिल रही है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड बलरामपुर के ग्राम जमुआंटांड की रहने वाली रंगोली सिंह ने बताया कि महतारी वंदन योजना हम महिलाओं के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू की गई अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत हर माह मेरे बैंक खाते में 01 हजार रूपये राज्य शासन द्वारा सहायता के रूप प्रदान की जा रही है। वे कहती हैं कि पहले घर का खर्चा हमारे घर के पुरुष चलाते थे।

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णत: प्रतिबंधित

बलरामपुर। मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नवीन मत्स्य पालन अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के समस्त नदियों, नालों तथा छोटे नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये हैं। सभी में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।

रतनजोत बीज खाकर आंगनबाड़ी 7 बच्चे हुए बीमार

कोंडागांव। ग्राम पंचायत बनजूगानी में रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह 7 बजे से ग्राम बनजूगानी के बच्चे आंगनबाड़ी गए हुए थे, जहां से लगभग 9 बजे ही छुट्टी दे दी गई। छुट्टी के बाद यह बच्चे अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 8 से 10 बच्चों ने रतनजोत पेड़ के बीज तोड़कर खा लिए और घर पहुंचने के बाद वे लगातार उल्टी करने लगे। परिजनों ने इसकी सूचना कार्यकर्ता को दी, जिसके बाद इन्हें संजीवनी 108 की मदद से जिला अस्पताल कोंडागांव लाया गया जहां 7 बच्चों का उपचार जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुखयारीन पोयाम ने बताया कि आज आंगनबाड़ी में यूनिसेफ का एक कार्यक्रम आयोजित होना था। इसलिए बच्चों को निधार्रित समय से पहले छुट्टी दे दी गई। सुपरवाइजर ऋतु देवांगन ने बताया कि बच्चे जब हॉस्पिटल आ गए तब उन्हें कार्यकर्ता ने सूचना दी। उन्होंने बताया कि सहायिका बच्चों को घर तक छोडऩे गई थी या नहीं यह उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल 7 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।

जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाला अपराधी गिरफ्तार

कांकेर। जिले के थाना चारामा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला की जिला बदर आदतन अपराधी गुलाब सिन्हा चारामा के कोरर चौक के पास घुम रहा है। सूचना पर चारामा पुलिस द्वारा सूचना की तस्दीक पर कोरर चौक पहुचे जहां पर गुलाब सिन्हा घुम रहा था। जिसे थाना लाकर पूछने पर गोल-मोल जवाब दिया और आने का कोई उचित कारण नही बताया। जिला बदर के संबंध में तात्कालिन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा 05 अक्टूबर 2023 को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5,6, अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये, अगामी एक वर्ष 05.10.2023 से 05.10.2024 तक के लिए जिला कांकेर एवं सीमावर्ती जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, मोहला मानपुर अम्बागढ चैकी, की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए हट जाने या चले जाने जिला बदर पारित किया गया था। जिला बदर के आदेश का उल्लघंन करने पर आरोपी को थाना चारामा में अपराध क्रमांक 98/2024 कायम कर विवेचना में लिया गया।

15 साल बाद पकड़ा गया आर्म्स एक्ट का आरोपी

कोरबा। कोरबा की सिविल लाइन रामपुर पुलिस ने आर्म्स एक्ट्स से जुड़े मामले में दीपक लकड़ा को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2009 में हथियार लेकर धमकाने पर उसे आरोपी नामजद किया गया था। उस समय से आरोपी फरार चल रहा था। कोरबा की कोर्ट ने उसके विरुद्ध स्थाई वारंट जारी किया था। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। ये पूरा मामला 2008 और 2009 की है जहाँ 39 वर्षीय दीपक लकड़ा सिविल लाइन थाना अंतर्गत सीएसईबी कॉलोनी में हाथ मे हथियार लेकर स्थानीय निवासी को डरा धमका रहा था पीड़ित की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे जेल भी दाखिल किया गया था जेल से जमानत में छूटने के बाद से वो छग कोरबा छोड़कर बाहर चला गया और बार बार जगह कई सालों तक बदलता रहा पश्चिम बंगाल में निजी कम्पनी में काम कर छुपा हुआ था जहाँ उसने अपना नाम भी बदल लिया था उसे वहा लोग दूसरे नाम से जानते है।

मुदरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन चालू होने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी

■ बेहतर गतिशीलता और दक्षता आएगी

बिलासपुर। मुदरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन का चालू होना इस क्षेत्र में यात्री और मालगाड़ी परिचालन दोनों की दक्षता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस रणनीतिक विस्तार का उद्देश्य बढ़ते माल यातायात से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना, अधिक रेल लाइन बनाकर यात्री गाडिय़ों के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करना है। इस विस्तार का एक प्राथमिक लाभ शहडोल क्षेत्र और सोहागपुर क्षेत्र की कोयला खदानों की साइडिंग में लोडिंग के लिए खाली मालगाडिय़ों की निर्बाध आपूर्ति की सुविधा है। इससे न केवल आपूर्ति सुचारू हो रही है, बल्कि जैतहरी में एमबीपीजे पावर प्लांट जैसे महत्वपूर्ण

औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन को भी बल मिलता है, जो कि रोजगार और आजीविका प्रदान करके स्थानीय समुदाय के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, मुदरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन चालू होने से अमलाई शहर में ओरिएंट पेपर मिल जैसे उद्यमों को लाभ मिलेगा और रुपौंद में सीमेंट लोडिंग में सुविधा होगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से जेके समूह द्वारा शुरू की गई पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

रेल लाइनों को तीसरी और चौथी करने जैसी पहलों के माध्यम से रेल अवसंरचना को बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रतिबद्धता यात्रियों और उद्योगों दोनों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके समर्पण को रेखांकित करती है। मुदरिया में आगामी नॉन-इंटरलाकिंग और सीआरएस निरीक्षणों से सीआईसी सेक्शन में क्षमता में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे उत्तरी भारत के लिए न्यू कटनी स्टेशन और पेंड्रा स्टेशन से आगे निर्बाध कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का निवेश न केवल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी है। छोटा महानदी नदी पर युद्ध स्तर पर चल रहा पुल संख्या 196 का निर्माण इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो इस क्षेत्र के लिए गतिशीलता और कनेक्टिविटी बढ़ाने को सार्थकता प्रदान करेगा।

मुदरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन का चालू होना, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सक्रिय दृष्टिकोण के साथ, समयबद्धता, दक्षता और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है स्टेशनों में सुरक्षा की निगरानी

बिलासपुर। मंडल रेल प्रशासन यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधाएं तथा सुरक्षा के साथ बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंडल के अंतर्गत अवस्थित स्टेशनों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री एक स्थान से दूसरे स्थानों के लिए यात्रा करते हैं।

यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रेल सुरक्षा बल एवं जीआरपी के ऊपर रहती है स्टेशन के सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिनकी मदद से रेलवे परिसरों की बेहतर संरक्षा औए सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है 7 सीसीटीवी की मदद से रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के कंट्रोल रूम से स्टेशनों के सभी गतिविधियों व सुरक्षा की निगरानी 24 घंटे की जा रही है 7यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा आपराधिक एवं संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के क्रम में निर्भया फंड के तहत मंडल के 09 स्टेशनों में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जिसमें रायगढ स्टेशन में 32, पेण्ड्रारोड स्टेशन में 16, अनुपपुर स्टेशन में 32, शहडोल स्टेशन में 16, अकलतरा स्टेशन में 12, चाँपा स्टेशन में 23, कोरबा स्टेशन में 9 सहित 7 स्टेशनों में सीसीटीव्ही कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। शेष 02 स्टेशनों जिसमें अम्बिकापुर स्टेशन में 14 तथा उमरिया स्टेशन में 15 सीसीटीवी लगाने का कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं जिसे अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। ये सभी सीसीटीवी कैमरे पूरे स्टेशन को कवर करने वाली एचडी प्रकार के तथा चेहरे पहचानने वाले साफ्टवेयर जैसी आधुनिक तकनीकी से लेस हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे विभागों की समीक्षा, 13 से 15 जून तक बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शासकीय कामकाज में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों के की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। विभागों की समीक्षा की बैठक 13 जून से शुरू होगी। वहीं बैठक 15 जून तक होगी। सीएम साय 13 जून को दोपहर एक बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, दोपहर तीन बजे से पशुधन विकास, मत्स्यपालन एवं दुग्ध महासंघ के काम-काज की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 14 जून को सुबह साढ़े 11 बजे से स्वास्थ्य विभाग और दोपहर तीन बजे चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बाद 15 जून को सुबह साढ़े। 11 बजे से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और दोपहर दो बजे से गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए मास्टरों ट्रेनरों का प्रशिक्षण 13 को

रायपुर। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राजधानी रायपुर में डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ 2024 के लिए 13 जून को मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपर आयुक्त भू-अभिलेख डॉ. संतोष देवांगन ने से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण इन्द्रावती भवन में तृतीय तल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल नंबर-05 में सुबह 10.30 बजे से प्रारंभ होगा। इस प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को भू-अभिलेख अधिकारी और भू-अभिलेख अधीक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित करते हुए प्रशिक्षण में उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष पद पर अरविन्द ओझा की नियुक्ति

रायपुर। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लोधी रोड़, दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में माननीय राज्य सभा सांसद कार्तिकेय शर्मा चेयरमैन श्री शशिकांत शर्मा वाइस चेयरमैन श्री सुखबीर शर्मा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. सी. पाण्डेय जी की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन शशिकांत शर्मा ने कहा कि अभी तक देश में केवल सात राज्यों में ही ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों से मांग करेगी कि देश के सभी राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड तथा परशुराम भवनों की स्थापना की जाए। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन श्री शशिकांत शर्मा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द ओझा को स्मृति चिन्ह एवं नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

आईटीआई छात्रावास अधीक्षक-अधीक्षिका के पदों पर भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक-अधीक्षिका के पदों पर अभ्यर्थियों का छठवें चरण का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को एसएमएस और व्हाट्सएप्प पर जानकारी दी गई है। दस्तावेज सत्यापन 13 जून को सुबह साढ़े 9 बजे से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर में किया जाएगा। छठवें चरण में रिक्त पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। कट ऑफ मार्क्स संचालनालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी अभ्यर्थी जानकारी के लिए संचालनालय की वेबसाइट https://cgiti.cgstate.gov.in/ और अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन के बाद संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस को दोपहर एक बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा/आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

रायपुर शहर में चलेंगी 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें, आम जनों को मिलेगी सुविधा

रायपुर। राजधानी रायपुर की जनता को जल्द

ही ई बसों से शहर में आने जाने की सुविधा मिलने वाली है । प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर को एक सौ नई बसें मिलेंगी। इन बसों के लगातार संचालन के लिए शहर के आमानाका और पंडरी में दो नए बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा और भी आसान होगी कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज आमानाका में स्थापित होने वाले बस डिपो का निरीक्षण किया और वहाँ की जा रही तैयारियों-निर्माण कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने ई बसों की चार्जिंग के साथ मेंटेनेंस के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ग़ौरतलब है कि रायपुर शहर को केंद्र सरकार की ओर से एक सौ नई ई-बसें मिलने वाली हैं। ये बसें बैट्री से चलेंगी । डिपो स्थलों पर इन बसों की बैट्री चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी है। पंडरी और आमानाका में बनने वाले सिटी बस डिपो बसों के लिए सेंटर पॉइंट होंगे । इन दोनों डिपो से ही शहर के अलग अलग स्थानों के लिए सिटी बसें चलेंगी।

बलौदाबाजार हिंसा मामले की होगी जांच : विजय शर्मा

गृहमंत्री ने लिया घटना का जायजा, कहा- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

रायपुर/भाटापारा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचकर तोड़फोड़ और आगजनी घटना का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से घटना की जानकारी ली। पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय और जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसानों का जायजा लिया। शर्मा ने घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उनके साथ खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि भारी संख्या में वाहनों को क्षति पहुंचाया गया है। जिनमें से कुछ अपने कार्य के लिए पहुंचे गरीब लोगों और अधिकारी कर्मचारी के होंगे। शासकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाया गया है, रिकॉर्ड रूम में न जाने कितने दस्तावेज जल चुके हैं। सरकारी सम्पति को तबाह करने वाले समाज के नहीं होते। पूरे प्रदेश में बाबा गुरुघासीदास को माना जाता है। वे श्वेत ध्वजवाहक हैं और शांति के प्रतीक हैं।

जानें क्या था मामला- बता दें कि पिछले महीने अराजक तत्वों ने अमर गुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचायी थी। इस पर पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर समाज के लोगों ने जांच की मांग की थी। शर्मा ने सीएम के निर्देश पर न्यायिक जांच की घोषणा की है। इस पर समाज के लोगों ने संतुष्टि जाहिर करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा था। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में सतनामी समाज के लोग कलेक्ट्रेट के पास बवाल मचाया। उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। कई वाहनों में आग के हवाले कर दिया। घटना के दौरान 20-30 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जिनमें से गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों को रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल शहर में स्थिति सामान्य है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान आईजी अमरेश मिश्रा, संजीव शुक्ला, कलेक्टर केएल चौहान, एसपी सदानंद कुमार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

पूर्व मंत्री डहरिया ने कहा- सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर डिप्टी सीएम साव बोले- होगी कठोर कार्रवाई

बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी में बीते दिनों जैतखाम में हुए तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई से असंतुष्ट सतनामी सामाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी उग्र और हिंसक हो गए। उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया साथ ही 100 से ज्यादा दोपहिया और 30 चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद शहर में 16 जून तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा कि सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। वहीं इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा घटना की जांच की शुरुआत हो गई है। समाज को बदनाम करने वाले तत्व पर कठोर कार्रवाई होगी। बलौदाबाजार घटना पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि जैतखाम काटने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। समाज ने न्यायिक जांच की मांग की थी। सही समय पर कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी ने समाज की कोई बात नहीं सुनी और धरना प्रदर्शन के दिन न्यायिक जांच की घोषणा की गई। सरकार की पूरी तरह लापरवाही है, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। सतनामी समाज के लोग हमेशा प्रताड़ित हुए हैं, नहीं ध्यान दिये जाने की वजह से ये आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसी घटना हुई, यह बेहद शर्मनाक है।

गृहमंत्री विजय शर्मा के सतनामी समाज के लोगों से बात करने वाले बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं और उनके समर्थकों को बुलाकर बैठक लिया गया। सरकार के कुछ लोगों के साथ बात कर लेना समाज के लोगों के साथ बात करना नहीं है। समाज के लोगों के साथ बात करनी चाहिए।

मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है। कल जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाये उतनी कम है। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। सीएम ने घटना की विस्तृत समीक्षा की है। उपद्रवियों पर कड़ी से करवाई के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री की समाज प्रमुखों से भी चर्चा हो रही है। मुस्तैदी से जांच की जा रही है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। आज तक छग में ऐसी घटना का इतिहास नहीं रहा। छग की शांति और सद्भावना से खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है।

इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव साव ने कहा कि घटना की जांच की शुरुआत हो गई है। गृहमंत्री देर रात तक घटना स्थल पहुंचे। घटना स्थल का अवलोकन किया है, शांति और सौहार्द बनाये रखने की अपील की है। समाज को बदनाम करने वाले तत्व पर कठोर कार्रवाई होगी।

सीएम साय ने बलौदाबाजार हिंसा में घायल जवान के बेहतर इलाज करने के लिये दिये निर्देश, अस्पताल पहुंचे अधिकारी

सीएम विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार हिंसा में घायल पुलिस जवान संदीप खलको के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उनके निर्देश पर खलको के बेहतर इलाज के लिए यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। आईजी संजीव शुक्ला, कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने अस्पताल का दौरा कर खलको का कुशलक्षेम पूछा। जवान की हालत खतरे से बाहर है। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए घटना के बारे में बताया। आइजी और कलेक्टर एसपी ने इलाज कर रहे डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन से भी चर्चा की और बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों ने बताया की घटना में खलको के जबड़े और आंख में चोट लगी है। उन्हें भर्ती कर जांच और इलाज शुरू कर दिया गया है। बाकी उनका स्वास्थ्य ठीक है। आईजी और कलेक्टर ने घायल जवान की सहायता के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। अधिकारियों ने घायल जवान के परिवार जनों से भी मुलाकात कर उन्हें ढाढस बंधाया। इस अवसर पर एसडीएम पीयूष तिवारी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

बलौदाबाजार हिंसा : भूपेश बघेल ने कहा- सरकार से हुई बड़ी चूक, राज्यपाल और राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए

रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। दिल्ली से लौटते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर कई आरोप लगाए।

पूर्व सीएम बघेल का कहना है कि सरकार से एक बड़ी चूक हुई है। सरकारी सिस्टम घटना को रोक पाने में विफल रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये अब तक सबसे बड़ी प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटना है। कलेक्टर और एसपी कार्यकाल जला देना सामान्य बात नहीं है। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि प्रदर्शन को इतना उग्र होने किसने दिया ?

बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया कि घटना को लेकर अब लीपापोती किया जा

रहा है। समाज के लोगों को सरकार शांत करा पाने में नाकाम रही है। न्यायिक जांच की घोषणा पहले क्यों नहीं की गई ? उनका कहना है कि सरकार से कानून व्यवस्था संभल ही नहीं रही। प्रदेशभर में लचर व्यवस्था है। गृहमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है कि खुफिया विभाग पूरी तरह फेल रहा है।

भूपेश बघेल ने कहा, सतनामी समाज के लोग सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। जैतखाम में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, जो वास्तविक आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हिंसा की घटना की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं समाज से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।

बता दें कि गिरौदपुरी के जैतखाम में तोड़फोड़ से आक्रोशित सतनामी समाज के हजारों लोग सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने निकले थे। इस दौरान झूमाझटकी और पथराव भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में आग लगा दी, जिससे सैकड़ों गाड़ियां जलकर राख हो गई।

कृषि विवि में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आज से

कृषि मंत्री नेताम करेंगे शुभारंभ, आम की 150 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 12, 13 एवं 14 जून को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ श्री रामविचार नेताम मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अनुज शर्मा, विधायक, धरसींवा, श्री मोतीलाल साहू, विधायक, रायपुर ग्रामीण एवं डॉ. संजय अलंग, कुलपति महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग उपस्थित रहेंगे।

राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 150 से अधिक किस्मों एवं आम से बने 56 व्यंजनों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता भी आयोजित है। इसके अतिरिक्त आम की सजावट

प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते है। इस प्रतियोगिता में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। राष्ट्रीय आम महोत्सव में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं। आयोजन के प्रथम दिवस 12 जून को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। इसके पश्चात सामान्यजनों के लिए प्रदर्शनी अवलोकनार्थ सायः 9 बजे तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी सामान्यजनों हेतु विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। आयोजन के द्वितीय दिवस आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 13 जून को 12 बजे से 4 बजे तक तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पाद एवं उनके विपणन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जायेगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर बढ़ सके। आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी।

राष्ट्रीय आम महोत्सव के अंतिम दिन प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ ही प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जायेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय फल आम जो कि आम जनता का प्रिय फल है उसकी समस्त सामान्य एवं खास किस्मों, विशिष्ट उत्पादों एवं भविष्य में अधिक उत्पादन के लिए रोजगार के साधनों की जानकारी सामान्य नागरिकों, महिलाओं विद्यर्थियों, नव उद्यमियों एवं कृषकों को प्रदान करना है। राष्ट्रीय आम महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभागी न्यूनतम 10 आम प्रति किस्म के साथ भाग ले सकते हैं। इस अवसर पर आयोजित आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता सामान्य जन न्यूनतम 250 ग्राम आम के उत्पाद को पंजीयन कर इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

छत्तीसगढ़ मे 36 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से मिली मुक्ति

रायपुर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवार की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 36 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

एक समय ऐसा था जब उच्च और उच्च मध्यम परिवारों के घरों में रसोई गैस कनेक्शन होता था। गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए ऐसी सुविधा जुटाना एक सपने जैसा था। गरीब परिवारों की महिलाओं को परिवार संभालने की जिम्मेदारी के साथ-साथ असुविधाजनक ढ़ंग से लकड़ी या कोयले के माध्यम से चूल्हे में खाना पकाना पड़ता था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की गरीब महिलाओं की दिक्कतें को समझते हुए तथा उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना की शुरूआत 2016 में की।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में छत्तीसगढ़ में अबतक 36 लाख से अधिक गरीब परिवार की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। रसोई गैस मिलने से किचन का वातावरण काफी सुविधाजनक हो गया है। महिलाओं को धुल धुएं से मुक्ति मिल गई है। खाना पकाने में उन्हें काफी कम समय लग रहा है। महिलाओं के समय में भी बचत हो रही है।

रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के ग्राम भुइयांपानी निवासी विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर परिवारों के 60 वर्षीय नान्हीबाई ने मुख्यमंत्री श्री

विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब उन्हें जंगल जाना नहीं पड़ता। ना ही मजबूरी में खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ती हैं। जंगल से लकड़ी लाने में जंगली जानवरों का खौफ रहता था। चूल्हे के धुंए से भी राहत मिल रही हैं। बैकुण्ठपुर निवासी हितग्राही 30 वर्षीय श्रीमती रामबाई, 55 वर्षीय श्रीमती मानकुंवर बाई, 25 वर्षीय श्रीमती दुर्गा, 35 वर्षीय फूलबासन बाई, 31 वर्षीय श्रीमती ऊषा बाई ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले भोजन बनाते समय धुआं के कारण खांसी और आंख से आंसू बहते थे। अब गैस-चूल्हा मिलने से इस समस्या से छुटकारा मिल गया है। श्रीमती फूलबासन बाई कहती है कि गैस चूल्हा से खाना बनाना काफी आसान हो गया है। बर्तन भी काले नहीं होते हैं। यह योजना परिवार के लिए और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। गैस चूल्हा होने से पेड़ की कटाई भी रूकेगी और हरियाली भी बने रहेगी।

सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की बढ़ेगी दक्षता : साव

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण व रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकों से रू-ब-रू होंगे। राज्य में पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी द्वारा रायपुर के नवीन विश्राम भवन में लोक निर्माण विभाग के रायपुर और दुर्ग संभाग के अभियंताओं के लिए इस चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें दोनों संभागों के विभागीय उप अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न संस्थाओं और निर्माण एजेंसियों के विषय विशेषज्ञ उन्हें इनका प्रशिक्षण दे रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति जब तक काम करता है, लगातार सीखता रहता है। समय के साथ

कार्यक्षेत्र की जरूरत बदलती है, नई तकनीकें आती जाती हैं। इनके अनुरूप हमें भी अपडेट होना पड़ता है। तभी हमारी उपयोगिता और प्रासंगिकता रहती है। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, तेज रफ्तार वाली गाडिया भी आ गई हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सड़क और पुल-पुलियों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन जरूरी है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर, टेंडर एग्रीमेंट, गुणवत्ता का निरीक्षण व नियंत्रण तथा कार्यों का भुगतान लोक निर्माण विभाग करता है। इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा मानक और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना भी विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभागीय अभियंता इस प्रशिक्षण के दौरान देश-दुनिया की नई तकनीकों और नए मानकों से रू-ब-रू होंगे और उन्हें फील्ड में अमल में लाएंगे। इस प्रशिक्षण से हमारे अभियंताओं की योग्यता, कार्यकुशलता और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। श्री साव ने इस वृहद प्रशिक्षण के आयोजन के लिए आईएएचई को धन्यवाद दिया।

लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के चार दिवसीय प्रशिक्षण में आईएएचई के निदेशक श्री संजीव कुमार, सीआरआरआई की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. लक्ष्मी परमेश्वरन और श्री सतेन्दर कुमार तथा एलिगेंट कन्सल्टेंट के प्रबंध निदेशक श्री आलोक पाण्डेय पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों के बारे में बताएंगे। आईएएचई के संयुक्त निदेशक श्री दिनेश कुमार शर्मा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री के.के. पीपरी और मुख्य अभियंता (सेतु बंध) श्री एम.एल. उरांव सहित सभी मुख्य अभियंता प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में मौजूद थे।

निरंतरता, अनुभव और उत्साह का संगम है मंत्रिमंडल

प्रो. संजय द्विवेदी

केंद्र सरकार का नया मंत्रिमंडल निरंतरता की गवाही देता है। यह बात बताती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी टीम पर भरोसा कायम है। प्रमुख विभागों में अपनी आजमाई जा चुकी टीम को मौका देकर मोदी ने बहुत गंभीर संदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल में अनुभव, उत्साह और नवाचारी विचारों के वाहक नायकों को जगह मिली है। यह मंत्रिमंडल गहरी राजनीतिक सूझबूझ वाले नायकों से संयुक्त है। लंबे समय तक राज्य सरकारों को चलाने वाले 7 पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार में शामिल हैं। कैबिनेट में नरेंद्र मोदी सहित सात पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। जिनमें मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह (उप्र), शिवराज सिंह चौहान (मप्र), जीतनराम मांझी (बिहार), एचडी कुमारस्वामी (कर्नाटक), मनोहरलाल खट्टर(हरियाणा), सर्वानंद सोनोवाल (असम) मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव और पिछली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एस.जयशंकर अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। आईएएस अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव अटलबिहारी वाजपेयी सरकार में उनके सचिव रहे,विविध अनुभव संपन्न वैष्णव सरकार में नवाचारों के वाहक हैं। पिछली सरकार उनके प्रदर्शन की गवाही है। इसी क्रम में नौकरशाह रहे हरदीप सिंह पुरी सरकार की शक्ति हैं। नितिन गडकरी का महाराष्ट्र सरकार से लेकर अब केंद्र में 10 साल का कार्यकाल सबकी नजर में है। देश में हुई परिवहन और सड़क क्रांति के वे वाहक हैं। वे केंद्र में सबसे लंबे समय तक परिवहन मंत्री रहने का रिकार्ड बना चुके हैं। भाजपा के पास अनुभवी मंत्रियों की टीम सरकार के संकल्पों की वाहक बनेगी, इसमें दो राय नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, जोएल ओराम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डा. वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी हस्ताक्षर बन चुके हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रभावी संचालन का रिकार्ड इनके नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह और अमित शाह इस सरकार के संकटमोचक हैं। राजनाथ सिंह के साथ जहां सहयोगी दलों का शानदार संवाद है, वहीं अमित शाह अपने कुशल राजनीतिक प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। इस सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री हैं। जबकि 2014 में 5 और 2019 में सहयोगी दलों के 4 मंत्री शामिल थे। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार में कुशल प्रबंधन की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव भी होने हैं। यही इस सरकार का पहला सार्वजनिक टेस्ट भी है। मंत्रिमंडल में प्रतिबद्धता, निरंतरता और वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए भी युवाओं को खास मौके दिए गए हैं। इसके साथ ही यह अखिल भारतीय चरित्र की सरकार भी है, केरल, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है। पांच अल्पसंख्यक समुदायों से भी सरकार में मंत्री बने हैं। साथ ही सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह समावेशी सरकार कही जा सकती है। अभी तक की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सुशासन को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन समान नागरिक संहिता, मुस्लिम आरक्षण, जातीय जनगणना, राज्यों को विशेष दर्जा जैसे मुद्दे मतभेद का कारण जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री के कद और उनकी छवि जरूर इन साधारण प्रश्नों से बड़ी है। सरकार के प्रबंधक इन मुद्दों से कैसे जूझते हैं,यह बड़ा सवाल है। सहयोगी दलों के साथ संतुलन और उनकी महत्ता बनाए रखते हुए चलना सरकार की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह अपने अभिभावकत्व और नेतृत्व से एनडीए को संभालते हुए काम प्रारंभ किया है। वे आसानी से साधारण विवादों का हल भी निकाल ही लेंगे।

गठबंधन के दबाव में काम करेंगे मोदी?

अशोक मधुप

9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने देश की सत्ता संभाल ली। प्रधानमंत्री के साथ ही 72 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना बाकी है, किंतु टीम में पुराने साथियों को जगह मिलना बताता है कि सब नरेंद्र मोदी की योजना के अनुसार हो रहा है। उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा और विश्वास है। हालांकि 2024 के इस आम चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। अब तक ठसक से सत्ता चलाने वाले नरेंद्र मोदी को गठबंधन के घटक दलों की सुननी और माननी होगी। वैसे शपथ ग्रहण की रात में भारत ने टी20 विश्व कप 2024 में इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ ही टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड बना दिए। यह जीत एक तरह से नई सरकार का स्वागत ही मानी जाएगी।

चुनाव से पूर्व ही नरेंद्र मोदी अपना एजेंडा बताते रहे हैं किंतु इस बार उनके सामने कई और भी चुनौतियां होगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के समय जम्मू में आंतकियों ने श्रद्धालुओं की बस हमला कर मोदी की नई सरकार के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। सरकार पहले ही आंतकवाद से मजबूती से जूझ रही है। उसे आंतकवाद की जड़े खत्म करने के लिए इस कार्यकाल में काम करना होगा। पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे आंतकियों के आकाओं के खात्मे के लिए भी उसे लगना होगा। हालांकि पाकिस्तान में ये काम चल रहा है। काफी समय ये वहां रह रहे भारत विरोधी आंतकियों को चुन-चुन कर कत्ल किया जा रहा है।

लोकसभा चुनाव के पहले ही भाजपा ने यह साफ कर दिया था कि मोदी सरकार 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर एजेंडे में शामिल होगा। उत्तराखंड में भाजपा सरकार पहले ही इसे लागू कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा था कि केंद्र की सत्ता वापस में लौटने के बाद भाजपा प्राथमिकता के साथ इसे आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब सहयोगी दल भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा पर इस निर्णय को वापस लेने पर दबाव बना सकते है। भाजपा के एजेंडे में वन नेशन, वन इलेक्शन भी शामिल हैं। इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी हैं। 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। एनडीए गठबंधन में इस बार जदयू और टीडीपी की भूमिका अहम है। ऐसे में वे भाजपा के इस एजेंडे पर भी रोड़ा बन सकते हैं।

तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का विस्तार भी शामिल है। नरेंद्र मोदी चुनावी कार्यक्रमों में यह कहते रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों के लिए %मोदी की गारंटी% पूरी की जाएगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने भविष्य के लिए अपने विजन को रेखांकित किया था। मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जाने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा तक अभूतपूर्व पहुंच पर जोर दिया। भाजपा के 2024 के घोषणापत्र में आयुष्मान भारत के कवरेज को 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाने का भी वादा किया गया है। इस एजेंडे को लागू करने में गठबधंन को कोई आपत्ति नहीं होगा और यह सरलता से लागू हो जाएगा।

चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपहसालार कहते घूमते रहे हैं कि सरकार बनी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का कब्जा होगा। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा के रोहतक में व्यापारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि आने वाले दो-तीन साल में किसी भी क्षण पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक बयान में पीओके को लेकर भारत के दावे को दोहराया था। सेरामपुर पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ तो सबसे आगे बढ़ गए। चुनाव के बाद के मोदी जी को तीसरे कार्यकाल पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज पाकिस्तान के लिए पीओके को भी बचाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले छह महीने के अंदर %पाक अधिकृत कश्मीर% भारत का हिस्सा होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि पीओके ले सकें। भाजपा के सिपहसालार की पाक अधिकृत कश्मीर पर चुनाव प्रचार के दौरान कब्जे की बात करते रहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी साधे रखी। किंतु कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के ये कहा कि भाजपायी पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चूड़ी नही पहन रखी।

पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप्पी साधे थे। किंतु पाकिस्तान ने चूडी नहीं पहन रखीं, पर उन्होंने जरूर कहा कि कांग्रेसी और कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखीं तो उसे पहना दी जाएंगी। प्रधानमंत्री के इस कथन से साफ होता है कि उनके सिपहसालारों के पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जे की घोषणा उनकी अपनी नहीं है। यह कहीं केंद्रीय नेतृत्व में पक रहा है और नई सरकार बनने पर वह इस पर कार्रवाई कर सकता है।

इतना सब होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार पर देशभर में जातिगत जनगणना कराने को लेकर दबाव बना सकते है। क्योंकि बिहार में पिछड़ी जातियों के अलावा दलित और मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। नीतीश अपने राज्य बिहार में इस जनगणना को करवा चुके है। वे लंबे समय से देश में इसे करवाने की डिमांड कर रहे है। क्योंकि अन्य विपक्षी दल चाहे वह कांग्रेस हो या फिर आरजेडी दोनों ही इस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। हालांकि भाजपा इसके विरूद्ध है। नीतीश कुमार वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे है। भाजपा में शामिल होने के पहले भी नीतीश ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने इस मांग को लेकर बिहार में अभियान चलाने की बात भी कही थी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते है। ये दोनों नेता अब अपनी इन मांगों को लेकर मोदी सरकार पर दबाव रहेगा। वैसे मोदी ऐसे दबाव से निपटना बखूबी जानते हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना को गठबंधन में लेकर ये दबाव कम किया जा सकता। चुनाव से पूर्व विपक्षी गठबंधन से जैसे नितीश कुमार पल्टी मार कर भाजपा के साथ आ गए, ऐसे ही विपक्ष में बैठे कई दल भाग सकतें हैं। बस इशारे की जरूरत है। मोदी पुराने राजनयिक हैं। कब किस हालात से कैसे जूझना है, वह जानते हैं। उम्मीद है कि वह अपनी सूझबूझ से सरकार को सरलता से पांच साल चलाते रहेंगे।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

सुबालोपनिषद् (भाग-7)

गतांक से आगे...

इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय भी अध्यात्म है, श्रोतव्य शब्द अधिभूत है और दिशाएँ अधिदैवत हैं। इन तीनों का मूल कारण नाड़ी है। श्रोत्र में, श्रोतव्य शब्द में, दिशाओं में, नाड़ी में, प्राण में, विज्ञान में, आनन्द में, हृदयाकाश में और सम्पूर्ण शरीर के अन्दर जो संचरित होता है, वह आत्मा है। इसी की उपासना करनी चाहिए।यह जरारहित, मृत्युरहित, भयरहित, शोकरहित और अनन्त है।

(उपर्युक्त के समान ही) नासिका अध्यात्म है, प्रातव्य (सूँघने के विषय) अधिभूत हैं और पृथिवी अधि दैवत है। नाड़ी उनका मूल स्थान है। जो नासिका में, प्रातव्य गन्ध में, पृथिवी में, नाड़ी में.... अनन्त है। (इसी प्रकार) जिह्वा अध्यात्म है, स्वादिष्ट पदार्थ अधिभूत हैं और वरुण अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो जिह्वा में, स्वाद लेने के रस में, वरुण में और नाड़ी में... अनन्त है।

(इसी प्रकार) त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श योग्य वस्तु अधिभूत है और वायु अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो त्वगिन्द्रिय में, स्पर्श किये गये पदार्थ में, वायु में और नाड़ी में अनन्त है।

(इसी प्रकार) मन भी अध्यात्म है, मन्तव्य (मन का विषय) अधिभूत है, चन्द्रमा अधिदैवत है। नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो मन में, जो मन्तव्य में, जो चन्द्रमा में, जो नाड़ी में अनन्त है।

(इसी प्रकार) बुद्धि अध्यात्म है, बोद्धव्य (बुद्धि का विषय) अधिभूत है, ब्रह्मा अधिदैवत हैं और %नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो बुद्धि में, बोद्धव्य में, ब्रह्मा में, जो नाड़ी में अनन्त है।

अहंकार अध्यात्म है, अहंकर्तव्य (अहं का विषय) अधिभूत है, रुद्र अधिदैवत हैं और नाड़ी इनका मूल स्थान है। जो अहंकार में, अहं के विषय में, रुद्र में, नाड़ी में ..अनन्त है।

क्रमशः ...

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस

सोनू गुप्ता

पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी, जिसका मकसद बाल श्रम को रोकना था। मालूम हो कि इसको मनाने के पीछे एक खास वजह यह थी कि बच्चों को मजदूरी न कराकर उनको स्कूलों की ओर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके।

मालूम हो कि बाल श्रम लगातार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसके कारण बच्चों का बचपन गर्त में जा रहा है और उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यह दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी संगठनों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है।

साल 1973 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने 138वें सम्मेलन में न्यूनतम आयु पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया, जिसका मकसद सदस्य देशों को रोजगार की न्यूनतम आयु बढ़ाने और बाल मजदूरी को समाप्त करना था। इसके 29 साल बाद साल 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने बाल श्रम रोकने का मुद्दा विश्व पटल पर रखा। साल 2002 में सभी देशों की सर्वसम्मति से एक कानून पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध घोषित किया गया। वर्तमान में इस श्रम संघ के लगभग 187 सदस्य देश शामिल हैं। बाल श्रम पर नियंत्रण को एक राष्ट्रीय मुद्दा मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी देश इस मुहिम से जुड़ेंगे।

भारत में बालश्रम की समस्या दशकों से प्रचलित है। भारत सरकार ने बालश्रम की समस्या को समाप्त क़दम उठाए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार बालश्रम तकनीकी सलाहकार समिति नियुक्त की गई। इस समिति की सिफारिश के अनुसार, खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है। 1987 में, राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनाई गई थी। मालूम हो कि बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई छोड़कर मजबूरी में मजदूरी चुनना पड़ता है। हालांकि, कई बच्चों को अपराध रैकेट द्वारा बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। इस दिवस को मनाने का विशेष महत्व बच्चों के अधिकारों पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है ताकि बाल श्रम को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, पिछले दो दशकों से पूरी दुनिया में बाल श्रम को कम करने के लिए लगातार पहल की जा रही है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान संघर्षों, संकटों और कोरोना महामारी ने विश्व में कई परिवारों को गरीबी में धकेल दिया है, जिसके कारण लाखों बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर होना पड़ा है।

चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा भारत

सुबीर भौमिक

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम का जवाब देने के लिए जैसे को तैसा अभियान चलाया है, यानी भारत भी तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदलेगा। चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने को लेकर नई दिल्ली को संदेह है कि बीजिंग ने पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपनी मजबूत दावेदारी दिखाने के लिए ऐसा किया है।

भारतीय सेना का सूचना युद्ध प्रभाग इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, जिसे कोलकाता स्थित ब्रिटिशकालीन एशियाटिक सोसाइटी जैसे प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। सेना ने अपने लोगो के साथ प्रसारित विस्तृत ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के सात स्थानों के नाम बदलने को चुनौती दी है और चीन द्वारा जिन 30 स्थानों के नाम बदले गए, उनके विरोध का प्रयास कर रही है। अब उन्होंने तिब्बत के 30 स्थानों की एक सूची को भी अंतिम रूप दे दिया है, तथा ऐतिहासिक अभिलेखों से भारतीय भाषाओं में उनके प्राचीन नामों को पुन: प्राप्त किया है। इन पंक्तियों के लेखक के पास यह सूची उपलब्ध है, जो मीडिया के जरिये सार्वजनिक की जाएगी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और विवादित सीमा के अन्य हिस्सों पर चीनी दावों के खिलाफ एक मजबूत जवाबी आख्यान प्रस्तुत करने के वैश्विक अभियान का हिस्सा है।

अब चूंकि केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसलिए चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के स्थानों का नाम बदलने का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को खत्म करने के लिए बदले के तौर पर किया जाएगा। सैन्य अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नए नाम व्यापक ऐतिहासिक शोध के आधार पर रखे जाएंगे।

पूर्व खुफिया ब्यूरो के अधिकारी बेनु घोष, जिन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्षों काम किया है और जिन्हें पर्वतारोहण में भी दिलचस्पी है, कहते हैं, जब भी ऐसा होगा, यह भारत द्वारा तिब्बत के प्रश्न को फिर से उठाने की तरह होगा। जब से बीजिंग ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया है, तब से भारत ने इसे चीनी हिस्सा माना है, लेकिन अब मोदी सरकार चीनी मानचित्रण और नामकरण संबंधी आक्रामकता को कम करने के लिए अपना रुख बदलने को तैयार है।

भारतीय सेना ने हाल के हफ्तों में इन विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में मीडिया के कई दौरे आयोजित करवाए हैं तथा मीडिया को उन स्थानीय लोगों से बात करने का मौका दिया है, जो चीनी दावों का कड़ा विरोध करते हुए कहते हैं कि वे हमेशा से भारत का हिस्सा थे। नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर इस अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि भारत का अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय और वैश्विक मीडिया के माध्यम से विवादित सीमा पर भारत के जवाबी आख्यान को आगे बढ़ाना है, जो ठोस ऐतिहासिक शोध और स्थानीय निवासियों के जनमत पर आधारित है। गौरतलब है कि इसी वर्ष कुछ समय पूर्व अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीन ने इस राज्य में एलएसी के पास के 30 स्थानों का नाम बदल दिया। हांगकांग स्थित एक दैनिक के अनुसार, प्रशासनिक प्रभागों की स्थापना और नामकरण के लिए जिम्मेदार चीनी असैन्य मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है, जिसे बीजिंग जंगनान कहता है। यह चौथी बार है, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का एकतरफा नामकरण किया है। इससे पहले उसने ऐसा वर्ष 2017, 2021 और 2023 में किया था। चीन द्वारा नाम बदले गए स्थानों की सूची में 11 आवासीय क्षेत्र, 12 पर्वतीय, चार नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और एक भूखंड है। इन नामों में चीनी, तिब्बती और पिनयिन अक्षर हैं, जो मंदारिन चीनी का रोमन वर्णमाला संस्करण है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मंत्रालय के बयान को उद्धृत किया है, जो कहता है कि भौगोलिक नामों के प्रबंधन पर राज्य परिषद (चीनी मंत्रिमंडल) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, हमने संबंधित विभागों के साथ मिलकर चीन के जांगनान में कुछ भौगोलिक नामों को मानकीकृत किया है।% बीजिंग ने वर्ष 2017 में अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के कथित मानकीकृत नामों की पहली सूची जारी की थी, फिर वर्ष 2021 में 15 स्थानों की दूसरी सूची जारी की और उसके बाद वर्ष 2023 में 11 स्थानों के नामों की एक और सूची जारी की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीनी कदम को बार-बार खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और मनगढ़ंत नाम रखने से यह वास्तविकता नहीं बदल जाती। वर्ष 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब चीन ने ऐसा प्रयास किया हो। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। मनगढ़ंत नाम रखने की कोशिशें इस सच्चाई को नहीं बदल पाएंगी।

अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को पुष्ट करने के लिए चीनी बयानों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के समक्ष कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने से हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार के दावे को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि यह सीमावर्ती राज्य भारत का स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में व्याख्यान देने के बाद अरुणाचल मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, यह कोई नया मुद्दा नहीं है। चीन के ये दावे शुरू से ही हास्यास्पद रहे हैं और आज भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में हम हमेशा से बहुत स्पष्ट और तार्किक रहे हैं। यह सीमा पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा बनेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है और जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए नाम बदलने के अभियान में शामिल हो गया है।

आज का इतिहास

1926 ब्राजील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया।
1939 बायरन नेल्सन ने यू.एस. ओपन जीता।
1942 अपने तेरहवें जन्मदिन पर, ऐनी फ्रैंक ने नीदरलैंड के नाजी कब्जे पर अपनी डायरी रखना शुरू कर दिया।
1952 तत्कालीन सोवियत संघ ने जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया।
1954 पोप पायस XII ने डोमिनिक सैवियो की 14 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च में सबसे कम उम्र के गैर-शहीद संत बनाने के लिए उनकी मृत्यु हो गई।
1963 अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मेडगर एवर्स कू क्लक्स क्लान के सदस्य बायरन डी ला बेकविथ से थे।
1964 दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा।
1967 वेनेरा 4 लॉन्च किया गया था। वीनस शुक्र की खोज के लिए सोवियत वेनेरा कार्यक्रम में एक जांच थी। किसी अन्य ग्रह के वातावरण का इन-प्लेस विश्लेषण करने के लिए यह पहली सफल जांच थी।
1968 यू.एस. में रोज़मरी की बेबी फिल्म का प्रकाशन किया गया।
1987 शीत युद्ध- बर्लिन की दीवार द्वारा बर्लिन के ब्रेंडेन बर्गर गेट पर एक भाषण के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव को इस दीवार को फाड़ने की चुनौती दी!
1990 रूस दिवस 12 जून को मनाया जाता है, जो रूसी संघ का राष्ट्रीय अवकाश है। यह 1992 से हर साल मनाया जाता है। रूसी संघ के पीपुल्स डेप्युटीज़ की पहली कांग्रेस ने जून में रूसी सोवियत फेडरेल सोशलिस्ट रिपब्लिक की राज्य संप्रभुता की घोषणा को अपनाया था।
1991 बोरिस येल्तसिन तत्कालीन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बनें।
1994 दुनिया के सबसे बड़े टिवनजेट विमान बोइंग 777 ने पहली उड़ान भरी।
1996 एच. देवेगौड़ा ने लोकसभा में विश्वास मत जीता और संयुक्त मोर्चा गठबंधन के प्रमुख के रूप में शासन किया। वह कर्नाटक के हासन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 वीं लोकसभा के सदस्य हैं और जनता दल (सेक्युलर) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।
2001 रॉबर्ट एडवर्ड डायर को ब्रिटिश सुपरमार्केट श्रृंखला टेस्को के खिलाफ छह महीने के लंबे पत्र बम अभियान के लिए 16 साल की सजा सुनाई गई थी।

बंगाल में राज्य प्रायोजित हिंसा एक बदनुमा दाग की तरह है

ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में हिंसा का बढ़ना, लोगों में डर पैदा होना, भय का वातावरण बनना, आम जनजीवन का अनहोनी होने की आशंकाओं से घिरा होना चिंताजनक भी है और राष्ट्रीय शर्म का विषय भी है। यही वजह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वे विपक्षी कार्यकर्ताओं को हिंसा से बचाने के लिए सुरक्षा दें। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव बाद की हिंसा पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई एवं ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चुनाव के बाद एवं लोकसभा चुनाव के प्रचार दौरान तृणमूल कांग्रेस ने व्यापक हिंसा, आतंक एवं अराजकता का माहौल बनाया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर जिस तरह के हिंसक हमले कर रहे हैं, वह लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग है। ममता बनर्जी ने चुनाव के महापर्व को हिंसक बना दिया था, उसने एवं उसके कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं से, हिन्दुओं से, हिन्दू मन्दिरों-भगवानों-संतों एवं हिन्दू पर्वों से नफरत का बिगुल हर मोड़ पर बजाया है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला चुनाव के पहले ही कायम हो गया था। राज्य में हिंसा की अनेक घटनाएं चुनाव के दौरान भी देखने को मिलीं और अब चुनाव समाप्त हो जाने के बाद भी देखने को मिल रही हैं, जिनमें ग्यारह लोगों की मौत होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका सीधा अर्थ है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के इशारे पर हो रही है। हैरानी नहीं कि अराजक तत्वों को बंगाल पुलिस का मौन समर्थन हासिल हो।

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने 'आतंक का राज' फैला दिया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोधी दलों और विशेष रूप से भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है, जब चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 19 जून तक बढ़ा दी गई है। ऐसा चुनाव बाद हिंसा की प्रबल आशंका को देखते हुए किया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की चार सौ कंपनियां तैनात हैं और फिर भी वहां व्यापक हिंसा हो रही है। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस हिंसा को कितने नियोजित ढंग से अंजाम दे रही है। इस हिंसा एवं अराजकता के बढ़ने के प्रबल आसार इसलिए हैं, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी हिंसा हुई, पूर्व के अन्य चुनावों में भी हिंसा का बोलबाला रहा है। ऐसी स्थितियों में बंगाल में लोकतंत्र की भावना एवं मर्यादा का खुला हनन हो रहा है। इतनी व्यापक हिंसा बंगाल पुलिस के मूकदर्शक बने रहने एवं उसके सहयोग के बिना अंसभव है। इसी के चलते तमाम भाजपा कार्यकर्ता और उसके समर्थकों की हत्या की गई थी। पूर्व की हिंसा एवं आतंक के समय ऐसा माहौल बनाया गया था कि कई लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पलायन करते हुए पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी थी। इन जटिल होती स्थितियों को देखते हुए न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, जो एक लोकतांत्रिक सरकार के लिये लज्जाजनक है।

पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार देश में एकमात्र ऐसी सत्तारुढ़ पार्टी बन गई है जिसका देश के संविधान, न्यायपालिका एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी एवं तानाशाही का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रक्रिया बन गयी है। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा

का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआइ को हिंसक घटनाओं की जांच करने को कहा था। इस जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई भी तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों के दुस्साहस का दमन नहीं कर सकी। इसका प्रमाण 2023 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई भीषण हिंसा से मिला था, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। इस लोकसभा चुनाव में भी हिंसा के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है। यह ठीक है कि चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यहां तक कहा कि यदि राज्य सरकार हिंसा पर लगाम नहीं लगा सकती तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में पांच साल तक तैनात करने का आदेश देना पड़ सकता है। उच्च न्यायालय की इस कठोर टिप्पणी के बाद भी ममता सरकार की सेहत पर शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वह सारा दोष विरोधी दलों पर मढ़ देती है। वास्तव में जब तक बंगाल में हिंसा के लिए ममता सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक राज्य के हालात सुधरने वाले नहीं हैं।

ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। चुनावों में जितनी हिंसा बंगाल में हुई, उतनी अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिली। बंगाल का लोकतंत्र तानाशाही मानसिकता से गुजर रहा है। इन स्थितियों से तो यही लगता है कि राजनीतिक वोट बैंक के लिए ममता संविधान एवं सुरक्षा-व्यवस्था की जितनी अवमानना कर सकती है, उसने की है और आगे भी वह करती रहेगी। चुनावों में ऐसी हिंसक एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियां लोकतंत्र पर एक धुंधलका है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है।

लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों के परिणामों ने पूरे देश को चौंकाया है उनमें पश्चिम बंगाल भी शुमार है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम इसलिये भी आश्चर्य में डाल रहे हैं कि वहां तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ व्यापक नाराजगी थी, ममता सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों पर घोटाले के आरोप लगे थे, संदेशखाली की महिलाओं पर हुआ अत्याचार देश भर में बड़ा मुद्दा बन गया था, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इर्दगिर्द ईडी का शिकंजा कसा हुआ था, ममता बनर्जी को सनातन विरोधी बताया जा रहा था, तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने चुनावों से ऐन पहले पाला बदल लिया था, तृणमूल कांग्रेस पर हिंसक एवं अराजक होने का तगमा लगा था, बावजूद ममता जीती। देखा जाये तो ममता बनर्जी की छवि जुझारू एवं कद्दावर नेता की रही है और वह अपनी पार्टी को जिताने के लिए जी-जान लगा देती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान खुद पर होने वाले राजनीतिक हमलों को वह अपने पक्ष में मोड़ लेने में माहिर हैं। इसके अलावा, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने विभिन्न राज्यों में सीटों का बंटवारा कर आपस में समन्वय बनाकर चुनाव लड़ा लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले ही सारी चुनौती झेली। वह अपने बलबूते चुनाव जीतने का माद्दा रखती है तो फिर हिंसा का सहारा क्यों लेती है? अराजकता फैलाकर अपने ही शासन को क्यों दागदार बनाती है? क्यों अपने प्रांत की जनता को डराती है, भयभीत करती है? क्या ये प्रश्न ममता की राजनीतिक छवि पर दाग नहीं है?

ममता एवं तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। मुद्दा चाहे रामनवमी पर हिंसा का हो या संदेशखाली में हिन्दू महिलाओं के साथ अत्याचारों का या साधु-संतों को डराने-धमकाने का। राज्य में शीर्ष संवैधानिक पद पर रहते हुए भी ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक, गैर-कानूनी एवं राष्ट्र-विरोधी कार्यों को अंजाम दिया है। बंगाल में तो भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, हिंसा की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगल रहा है। ममता अपनी जातियों, गुरुपों और वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं-- देश को नहीं। दुनिया के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी। बंगाल में आम जनजीवन की सार्थकता ही नष्ट हो रही है।

गठबंधन सरकार की चल पड़ी गाड़ी

राज कुमार सिंह

आखिरकार नरेंद्र मोदी ने पं. जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार तीन बार देश की सत्ता संभाली थी। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने नौ जून की शाम राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर पंडित नेहरू के लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। 2014 और 2019 में अकेले दम बहुमत मिल जाने के बावजूद भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ एनडीए सरकार बनाई थी, पर इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे छूट जाने के चलते गठबंधन सरकार मजबूरी बन गई। मजबूरी ज्यादा बड़ी सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस बार भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है, बल्कि गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी भी हैं, जो गठबंधन राजनीति के माहिर सौदेबाज माने जाते हैं। इस लिहाज से नौ जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेनेवाली मंत्रिपरिषद पर नजर डालें तो कहा जा सकता है कि वह अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे। हां, एनसीपी के अजित पवार गुट के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने से अवश्य महाराष्ट्र की भावी राजनीति को ले कर कुछ कयास लगाए जा सकते हैं। मात्र एक लोकसभा सीट जीत पाए उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसे अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रफुल्ल ने अपना डिमोशन बताते हुए अस्वीकार कर दिया। एक लोकसभा सीट के बल पर अजित पवार सौदेबाजी कर पाने की स्थिति में नहीं। सो, मोदी सरकार में उनकी एनसीपी की कोई हिस्सेदारी नहीं, पर इस सबका इसी साल अक्तूबर में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

वैसे आंकड़ों की बात करें तो चुनाव हार जाने समेत कई कारणों से पिछले मोदी मंत्रिमंडल के कुल 37 चेहरों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि 33 नए चेहरों की एंट्री हुई है। नए चेहरों में सहयोगी दलों के चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हैं। पिछली सरकार में चाचा पशुपति पारस को सत्ता सुख देनेवाली भाजपा ने इस बार भतीजे चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन किया था। लोक जनशक्ति बिहार में गठबंधन में मिली सभी पांच लोकसभा सीटें जीत गई तो चिराग कैबिनेट मंत्री बना दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन में मिली दोनों लोकसभा सीटें जीतने पर जयंत के हिस्से स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद ही आया। राज्यवार देखें तो बिहार के कुल आठ मंत्रियों में से चार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के नौ मंत्रियों में से अकेले राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी कुल छह मंत्री बनाए गए हैं। इस बार मोदी मंत्रिमंडल के कुल 72 सदस्यों में से लगभग दस प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से 42 मंत्री बनाए गए हैं।

सर्वमत और सुशासन से बनेगा विकसित भारत

प्रो. संजय द्विवेदी

लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी भले ही सीटों के मामले में अपने घोषित लक्ष्य से पीछे रह गए हों, किन्तु चुनौती स्वीकार करने की उनकी जिजीविषा स्पष्ट है। पिछले तीन दिनों से उनके भाषण, बाडी लैंग्वेज बता रही है कि वे राजग की सरकार को उसी अंदाज से चलाना चाहते हैं, जैसी सरकार वे अब तक चलाते आए हैं। सहयोगी दलों से मिली पूर्ण आश्वस्ति के पश्चात मोदी ने अपने नेता पद पर चयन के बाद बहुमत से नहीं बल्कि सर्वमत से सरकार चलाने की बात कही है। वैसे भी चंद्रबाबू नायडू तथा नीतिश कुमार की ज्यादा रूचि अपने राज्यों की राजनीति में हैं। इसलिए सीधे तौर पर दो बड़े सहयोगी दलों तेलुगु देशम और जनता दल (यूनाइटेड) से कोई तात्कालिक चुनौती नहीं है। इसके साथ ही सुशासन मोदी, नायडू और नीतिश तीनों की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पिछले 22 वर्षों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर रहते हुए सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनमें सबको साथ लेकर चलने की अभूतपूर्व क्षमता है। सुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस उनकी कार्यशैली है। यह बात उन्होंने इस बार भी स्पष्ट कर दी है। लंबे नेतृत्व अनुभव ने उनमें साथियों के प्रति सद्भाव और अभिभावकत्व भी पैदा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए एनडीए का हर एक सांसद समान है। मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब यह बात काफी कही गई थी कि उन्हें दिल्ली की समझ नहीं है। विदेश नीति जैसे विषयों पर क्या मोदी नेतृत्व दे पाएंगे। जबकि पिछले 10 वर्षों में मोदी ने इन दोनों प्रारंभिक धारणाओं को खारिज किया। ऐसे में गठबंधन सरकार का नेतृत्व वे सफलतापूर्वक करेंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।

सत्ता के संकटों और सीमाओं के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अपने विजन और नेतृत्व क्षमता से लंबी लकीर खींची है। गहरी राष्ट्रीय चेतना से लबरेज उनका व्यक्तित्व एनडीए की चुनावी सफलताओं की गारंटी बन गया है। अब जबकि एनडीए के लगभग 303 सांसद हो चुके हैं, तब यह मानना ही पड़ेगा यह सरकार आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण की योजनाएं लागू करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा की राज्य सरकारें मोदी मैजिक का ही परिणाम है। केरल में खाता खोलने के साथ तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक के परिणाम दक्षिण भारत में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता बताते हैं। इन परिणामों में नरेंद्र मोदी की छवि और उनका परिश्रम संयुक्त है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र से गंभीर नुकसान के बाद भी सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा को जिताकर ले आना और एनडीए को बहुमत दिलाने में उनकी खास भूमिका है। एनडीए सांसद और सहयोगी दल भी मानते हैं उन्हें मोदी की छवि का फायदा अपने-अपने क्षेत्रों में मिला है। 10 साल के सत्ता विरोधी रूझानों के बाद भी अन्य क्षेत्रों में विस्तार करते हुए भाजपा और एनडीए अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे, यह साधारण बात नहीं है।

राजग ने चुनावी जंग में मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटें जीत लीं। बावजूद इसके अपराजेय समझे जाने वाले मोदी-योगी ब्रांड को उत्तर प्रदेश में बहुत गहरा झटका लगा है। प्रधानमंत्री की वाराणसी में जीत के अंतर को भी विरोधी रेखांकित कर रहे हैं। अयोध्या की हार मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन गयी है। जाहिर तौर पर इसे लोकतंत्र की खूबसूरती ही मानना चाहिए। इसलिए इसे जनादेश कहते हैं। आरक्षण और संविधान बदलाव के भ्रामक प्रचार ने जैसा उत्तर प्रदेश में असर दिखाया है, संभव है बिहार में चिराग पासवान और जीतनराम मांझी गठबंधन में न होते तो वहां भी ऐसा ही नुकसान संभावित था।

कांग्रेस और उसके गठबंधन को निश्चित ही बड़ी सफलता मिली है। इसके चलते संसद और उसके बाहर मोदी सरकार को चुनौतियां मिलती रहेंगी। विपक्ष का बढ़ा आत्मविश्वास क्या आनेवाले समय में सरकार के लिए संकट खड़ा कर पाएगा, इसे देखना रोचक होगा।

भारतीय लोकतंत्र वैसे भी निरंतर परिपक्व हुआ है। सर्वसमावेशी होना उसका स्वभाव है। सबका साथ, सबका विकास ही मोदी मंत्र रहा है। बाद में मोदी ने इसमें दो चीजें और जोड़ीं सबका विश्वास और सबका प्रयास। गठबंधन सरकार चलाने के लिए इससे अच्छा मंत्र क्या हो सकता है। मोदी और उनकी पार्टी ने विकसित भारत बनाने का कठिन उत्तरदायित्व लिया है, वे इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे तो यही बात भारत मां के माथे पर सौभाग्य का टीका साबित होगी।

महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम अनपेक्षित तो नहीं!

अमिताभ श्रीवास्तव

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनेक शीर्ष नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का परिणाम 45 सीटों से कम नहीं आंका, लेकिन चुनावी हवा के संकेत साफ थे कि इस बार आशाओं पर पानी फिर सकता है। अनेक नेता अपने आंकड़ों के दावों की गाड़ी को बमुश्किल 40 तक पहुंचा रहे थे तो दूसरी ओर कुछ राजनीति के पंडित नतीजा तीस के आस-पास बता कर रुक जा रहे थे।

मतदान बाद 'एक्जिट पोल' ने 'फिफ्टी-फिफ्टी' का फार्मूला सामने रखकर 20-25 सीटों के मिलने की संभावना से कुछ हद तक सच्चाई बयान कर दी। हालांकि यह कड़वी सच्चाई थी, मगर परिणाम बाद इसे पीने के लिए महायुति को तैयार होना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी बार-बार किसी बड़ी संख्या की बात करने से बचते हुए अपने बेहतर प्रदर्शन पर विश्वास कर रही थी। कुछ हद तक नतीजों ने उसकी ही बात को सच साबित कर यह सिद्ध कर दिखाया कि उसके प्रयास परिणामकारक रहे।

यदि राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के गुरुवार को दिए गए बयान को गंभीरता से लिया जाए तो उसमें एक संदेश साफ है कि चुनावी मुकाबलों में कहीं-न-कहीं भाजपा कमजोर रह गई। जिसे दूर करने के लिए फड़णवीस उपमुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं। स्पष्ट था कि लोकसभा चुनाव जीतने में भाजपा के सामने जितनी मुश्किलें थीं, वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रदर्शन से दूर नहीं हो सकती थीं।

उधर, जब से राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से उसे केंद्र के साथ जोड़ा गया। मराठा आरक्षण का मामला हो या फिर किसानों की समस्या, हर बार मांगों को केंद्रीय नेतृत्व से सुलझाने के लिए कहा गया। केंद्र को भरोसा रहा कि राज्य अपने स्तर पर अपनी परेशानियों को दूर करने में सफल हो जाएगा, लेकिन राज्य तो कोई हल निकाल नहीं पाया और आंदोलनकारियों का गुस्सा केंद्र तक जरूर पहुंच गया।

यहां तक कि घोषणा होने के पहले से चुनाव में खलल डालने की तैयारी शुरू हुई। जिसे दबाने के लिए

चुनाव से आंदोलन का सीधा संबंध नाकारा गया। फिर भी एक-दो बैठकों में सत्ताधारियों के खिलाफ चिंगारी भड़की, जो अनेक स्थानों पर विरोधी मतों में परिवर्तित हो गई। मराठवाड़ा के नांदेड़, बीड़, अहमदनगर, जालना और छत्रपति संभाजीनगर में मतों का प्रभाव पड़ने की सीधी आशंका रही। परिणामों का नांदेड़, बीड़, अहमदनगर और जालना में सीधा असर दिखा।

मराठा आरक्षण के अलावा किसानों की समस्याएं इतनी मुखर हो चुकीं थीं कि नासिक में प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में प्याज व्यापारियों ने नारेबाजी कर डाली। मराठवाड़ा में पानी से लेकर सोयाबीन, तुअर, कपास आदि की फसलों के समक्ष संकट परेशान करने वाला रहा। विपक्ष ने ग्रामीण भागों में किसानों की समस्या और आरक्षण आंदोलन को उठाया तो शहरी भाग में महंगाई और बेरोजगारी की बात पर आम राय बनाई।

सारे मामले केंद्र से जुड़े थे, जिसका समाधान राज्य सरकार के पास नहीं था। यहां तक कि विपक्ष अपने प्रचार में जो कहानियां (नैरेटिव) बना रहा था, वे मतदाता के मन में घर कर रहीं थीं। दूसरी ओर सत्ताधारी केवल आलोचना से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। संविधान बदलाव की बात भी बहुत आसानी से लोगों की समझ में आयी और वह सत्ताधारियों के चार सौ पार के लक्ष्य से जोड़कर पक्की हो गई।

लिहाजा प्रचार की बातें तथ्यात्मक कहानियों (नैरेटिव विथ लॉजिक) के रूप में परिवर्तित हो गईं। बावजूद इसके महायुति के पास सिवाय विपक्ष की बातों को झूठी ठहराने और अपनी ईमानदारी का बखान करने से अधिक कुछ नहीं था। बीते अनेक चुनावों में यह भी देखने में आया कि राज्य में भगवा गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई अधिक मतभेद उत्पन्न नहीं हुए।

इस बार महायुति की सीटों का बंटवारा आधे चुनाव तक चलता रहा। उसके बाद कुछ उम्मीवारों के नाम तो अंत में ही सामने आए। वरिष्ठ अधिवक्ता उज्वल निकम जैसा नाम उन्हीं में से एक था। वहीं दूसरी ओर अनेक नाम ऐसे भी थे, जिनको बदलने की जरूरत थी। उनको लेकर मतदाताओं के मन में निजी और सरकार विरोधी नाराजगी थी। ऐसे में विकल्प वही हो सकता था, जो नया हो और मतदाता को स्वीकार्य हो।

कुछ स्थानों पर नाम बदलने के परिणाम भी मिले, लेकिन वकील निकम का नाम ऐन वक्त पर सामने आना कांग्रेस की स्थापित उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ की तुलना में उचित नहीं था। महायुति की तुलना में महाविकास आघाड़ी ने आरंभ से ही सूझबूझ और संयम का परिचय दिया, जिसका लाभ उन्हें पहले ही दौर से मिला। उन्हें विदर्भ से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक आपसी तालमेल और परिस्थिति का काफी आसानी के साथ अनुमान लगा, जिससे सामने आए परिणामों के प्रति उनकी उम्मीद और वास्तविकता गलत साबित नहीं हुई।

यही कारण है कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद आरोप-प्रत्यारोप का कोई दौर आरंभ नहीं हुआ है। उपमुख्यमंत्री ने अधिक जिम्मेदारी से अगले चुनाव में ध्यान केंद्रित करने के लिए पद से हटने की पेशकश की है, समर्थकों को अस्वीकार्य है। दूसरी ओर महायुति पराजय की सामूहिक जिम्मेदारी मान रहा है। किंतु परिणामों के बाद से साफ है कि महाराष्ट्र में महायुति के साथ ऐसा खेल हो गया, जो आंखों से दिखाने के बाद भी उसका कोई समाधान दिख नहीं रहा था।

भविष्य में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनको लेकर सतर्कता इतनी ही बरतनी होगी कि हार से पहले पराजय के दृश्य न दिखने लगे। हालांकि उदारवादी दृष्टिकोण से अब यह भी कह देने में कोई बुराई नहीं है कि चुनाव में हार-जीत तो लगी ही रहती है। लेकिन इस बार हार इतनी भी हल्की नहीं कि उसे परंपरागत सोच से पचा लिया जाए।

अखिलेश के सामने बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती

अजय बोस

देश के सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) ने अविश्वसनीय छलांग लगाई है। पिछली बार पांच सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार पांच गुना से ज्यादा 37 तक पहुंच गई है। यह इस पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सपा ने 2004 में अनुभवी नेता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 35 सीटें जीती थीं। अपने पिता के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना अखिलेश के लिए व्यक्तिगत बड़ी सफलता है, जिनकी अक्सर राजनीतिक सूझबूझ और संगठनात्मक कौशल की कमी के लिए आलोचना की जाती रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपना मतदान प्रतिशत 33.59 तक पहुंचा दिया और 2019 के चुनाव में 62 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी (33 सीट) को दूसरे स्थान पर खिसका दिया। हालांकि अतीत में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करने का समाजवादी पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, फिर भी अखिलेश ने राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अखिलेश शुरुआत में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जमीन स्तर पर चर्चा करने के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मन बनाया। अखिलेश का पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) मुद्दा, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर गया। जहां गैर-यादव पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का महत्वपूर्ण गठजोड़ बनता है। यादव मतदाताओं की निष्ठा के प्रति आश्वस्त और यह जानते हुए कि मुसलमानों के पास समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को वोट देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, उन्होंने गैर-यादव पिछड़ी और दलित जातियों के लिए अपना रास्ता ही बदल लिया। यद्यपि यादवों और मुस्लिमों की पार्टी का ठप्पा लगा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चार मुस्लिम और पांच यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों, जैसे कि निषाद और कुर्मियों के साथ-साथ दलितों को 27 टिकट दिए। महत्वपूर्ण तो यह है कि दलितों को न केवल आरक्षित सीटों पर, बल्कि फैजावाद जैसी सामान्य श्रेणी की सीट पर टिकट दिया, जहां अयोध्या में राममंदिर है, वहां समाजवादी पार्टी के अनुभवी दलित नेता अवधेश प्रसाद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीबी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने से अखिलेश को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन वह इससे घबराए नहीं, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इस चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है, तो यह मायावती और बहुजन समाज पार्टी का शायद अंतिम राजनीतिक पतन है, जिन्होंने डेढ़ दशक पहले भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का वादा किया था। बहनजी की पार्टी का वोट प्रतिशत एकल अंक (9.39 फीसदी) में आ गया है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन से भी ज्यादा निराशाजनक है। 2014 में भी बसपा कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसे 20 फीसदी वोट मिले थे। बहनजी के लिए सबसे अधिक अपमानजनक तो नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनके प्रतिद्वंद्वी दलित नेता और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की जीत रही। चंद्रशेखर ने आश्चर्यजनक रूप से डेढ़ लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती और बसपा द्वारा रिक्त किए गए राजनीतिक स्थान पर चंद्रशेखर आजाद कब्जा कर पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में आजाद का भविष्य है, जबकि मायावती अब बीता हुआ कल हैं। जहां तक सपा की बात है, तो वह भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। यह सफलता अखिलेश के लिए अवसर लेकर आई है, तो चुनौतियां भी साथ में हैं, क्योंकि देश में फिर से गठबंधन के राजनीतिक युग की वापसी हुई है। उनके पिता राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति से अधिकतम लाभ उठाने में माहिर थे। अब बेटे की बारी है।

गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ इस तरह रखें अपना ख्याल, मां और बच्चा दोनों रहेंगे हेल्दी

तमाम स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मियों में अपना और गर्भ में पलने वाले बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रहे हैं, जिनको फॉलो कर आप अपना और बच्चे का ख्याल रख सकती हैं।

क्योंकि गर्मी में जरा सी लापरवाही करने से व्यक्ति लू की चपेट में आ सकता है। खासकर इस मौसम में प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होने पर पूरी हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। शरीर में पानी की कमी होने पर चक्कर आना, हार्ट रेट बढ़ना, बीपी लो होना और गंभीर मामलों में बेहोशी तक आ सकती हैं।

गर्मी के मौसम में हर कोई धूप और भीषण गर्मी से परेशान रहता है। इस मौसम में हर व्यक्ति को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। क्योंकि गर्मी में जरा सी लापरवाही करने से व्यक्ति लू की चपेट में आ सकता है। खासकर इस मौसम में प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होने पर पूरी हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। शरीर में पानी की कमी होने पर चक्कर आना, हार्ट रेट बढ़ना, बीपी लो होना और गंभीर मामलों में बेहोशी तक आ सकती हैं।

इस तरह की तमाम स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना और गर्भ में पलने वाले बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन टिप्स को फॉलो कर आप गर्मियों में अपना और गर्भ में पलने बच्चे का ख्याल रख सकती हैं।

खुद को रखें हाइड्रेट

गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाएं खुद को हाइड्रेट रखें। क्योंकि शरीर में पानी की कमी से तमाम समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पिएं। आप अपनी डाइट में लिक्विड चीजों को शामिल करें। इसके अलावा आप तरबूज और खीरे आदि का भी सेवन कर सकती हैं। क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है।

डाइट में शामिल करें हेल्दी चीजें

बता दें कि गर्मी के मौसम में सिर्फ सलाद का सेवन ही काफी नहीं होता है। बल्कि आपको हेल्दी चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए और अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए। आप गर्मी में प्रेग्नेंसी के दौरान जूस, सब्जियों और फल आदि का सेवन करना अच्छा माना जाता है। प्रेग्नेंसी के दौरान स्पाइसी चीजों से भी दूर रहें। क्योंकि गर्मियों में स्पाइसी खाने से तबियत बिगड़ने की अधिक संभावना रहती है।

न करें सॉल्टी फूड का सेवन

प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मी के मौसम में नमक का कम सेवन करना चाहिए। क्योंकि नमक की अधिकता होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जोकि मां और बच्चे दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बता दें कि नमक का अधिक सेवन करने से शरीर से पानी जल्दी निकल जाता है। सॉल्टी फूड में कुकीज और चिप्स आदि शामिल है।

ठंडी जगह पर बिताएं समय

गर्मी के मौसम में प्रेग्नेंसी के दौरान असहजता बढ़ सकती है। वहीं कुछ महिलाओं को उल्टी और जी मिचलाने की समस्या हो सकती है। वहीं गर्मियों में इस समस्या को ट्रिगर कर सकती है। इससे बचने के लिए आप ठंडे स्थान पर अधिक समय बिताएं। अगर घर में एसी लगी है, तो उस कमरे में समय बिताएं। लेकिन कमरे का तामपान सामान्य होना चाहिए। क्योंकि कमरे का टेंपरेचर अधिक ठंडा होगा, तो बाहर के गर्म तापमान में आपकी तबियत खराब हो सकती है।

आराम जरूर करें

कई महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत नींद आती है। हालांकि गर्मियों में आराम करने का मन नहीं करता है। गर्मी के मौसम में अधिकतर समय एसी में रहने का मन करता है। लेकिन इस दौरान आराम जरूर करें। क्योंकि आराम करना बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।

एक्सरसाइज करें

गर्भावस्था के दौरान एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि गर्मियों में आउटडोर एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। वहीं शाम के समय धूप ढलने के बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंसी में एक्सरसाइज करने में समस्या हो तो आप हल्की-फुल्की वॉक भी कर सकती हैं। इससे मां और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है।

दिन की शुरुआत करें ऐलोवेरा जूस पीकर

आमतौर पर ऐलोवेरा जेल का इस्तेमाल स्किन केयर के लिए जरुर किया होगा। क्या कभी आप ने अपनी सेहत के लिए ऐलोवेरा जूस पिया है। यदि नहीं तो आप इसके फायदे जानकर दंग रह जाएंगे। दरअसल ऐलोवेरा जूस कई प्रकार के विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसके जूस के सेवन से बॉडी हेल्दी रहता है।

ऐलोवेरा का पौधा हर एक घर में पाया जाता है। यह पौधा ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता लेकिन फिर भी गजब के फायदे देता है। दरअसल, यह घर की हवा शुद्ध करता है, घर को सुंदर बनाता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आमतौर पर ऐलोवेरा जेल का इस्तेमाल त्वचा की खूबसूरती निखारने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐलोवेरा जूस पीना आपकी सेहत के लिए कितना फायदा होता है। इसमें कई विटामिन और मिनरल, जैसे - विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि से भरपूर होने की वजह से इसका जूस पीने से सेहत से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने और उनसे बचाव करने में काफी मदद मिलती है।

पाचन क्रिया इम्प्रूव होती है

लैक्सेटिव गुण होते हैं, यानी यह आंतों को साफ करने मदद करता है। इसका जूस पीने से कब्ज की समस्या दूर होती और आंतें भी स्वस्थ रहती है। यह पाचन संबंधित समस्याओं जैसे एसिडिटी और ब्लोटिंग से भी राहत मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें कि ऐलोवेरा जूस का सेवन अधिक न करें।

ब्लड शुगर लेवल होगा ठीक

ऐलोवेरा जूस प्रीडायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे पीने से फास्टिंग शुगर लेवल कम करने में मदद मिलती है। इसके सेवन से डायबिटीज में मदद मिलती है। हालांकि, इसकी मदद से डायबिटीज से नहीं बचा जा सकता। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरुरी है।

मसूड़ों के लिए हेल्दी

ऐलोवेरा जूस मसूड़ों से जुड़ी परेशानियों को कम करने में मदद करता है। जूस के सेवन से सूजन और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसी वजह से ऐलोवेरा जूस पीने से ओरल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है।

गर्मियों में समर कंजंक्टिवाइटिस की समस्या से हो सकते हैं परेशान

गर्मियों के मौसम में हमारा स्वास्थ्य कई तरीके से प्रभावित होता है। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप का सीधा असर सेहत पर देखने को मिलता है। आज हम आपको समर कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बताने जा रहे हैं।

गर्मियों के मौसम में हमारा स्वास्थ्य कई तरीके से प्रभावित होता है। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप का सीधा असर सेहत पर देखने को मिलता है। यही कारण है गर्मियों में कई बीमारियां और समस्याएं होने लगती हैं। वहीं इस मौसम में हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉस्शन लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में कंजंक्टिवाइटिस आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि अधिकतर मानसून में यह समस्या लोगों को अपना शिकार बनाती है।

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, समर कंजंक्टिवाइटिस को पिंक आई भी कहा जाता है। वहीं गर्म मौसम में कंजक्टाइवल इरिटेशन होता है। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन सभी के अलग-अलग लक्षण व कारण होते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको समर कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बताने जा रहे हैं।

वायरल कंजंक्टिवाइटिस

यह वायरल एडेनोवायरस जैसे वायरस के कारण होता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस के लक्षणों में आंखों का लाल होना, आंखों का किरकिरापन और पानी निकलना आदि शामिल है। वहीं संक्रमण के अधिक बढऩे से रेस्पिरेटरी संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस

आपको बता दें कि पालतू जानवरों की फर या बाल, धूल और पोलन आदि से होने वाली एलर्जी से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके होने पर आंखों में सूजन, पानी जैसा डिस्चार्ज, खुजली और लालिमा जैसी समस्या हो सकती है।

इरिटेंट कंजंक्टिवाइटिस

इरिटेंट कंजंक्टिवाइटिस हवा, धुएं या क्लोरीन जैसे उत्तेजक पदार्थों के कारण होने वाली जलन से होता है। इसमें आंखों में दर्द, लालिमा और आंसू आने लगते हैं।

बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस

बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस स्टैफिलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने पर हरे या पीले रंग का गाढ़ा डिस्चार्ज और आंखों में लालिमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं सोने के दौरान पलकें चिपक जाती हैं। यह वायरस आसानी से फैल सकता है।

ऐसे करें बचाव

कंजंक्टिवाइटिस से खुद का बचाव करने के लिए एंटीहिस्टामाइन और एलर्जी से दूर रहना चाहिए। आमतौर पर वायरल कंजंक्टिवाइटिस खुद से सही हो जाता है, लेकिन आप ठंडी सिकाई और आंखों को चिकनाई देने वाली दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होने पर पीड़ित व्यक्ति को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप आंखों को साफ पानी से धोएं और जलन पैदा करने वाले पदार्थों से दूरी बनाकर रखें। कंजंक्टिवाइटिस से बचने के लिए स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। बार-बार हाथों को धोने और आंखों को छूने से

भागदौड़ भारी लाइफ के बाद भी महिलाएं खड़े होकर करें ये 4 योगासन

योग करना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। योगा करने से मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे ऐसे 4 योगासनों के बारे में जिन्हें जरुर करना चाहिए।

अक्सर महिलाओं के पास खुद के लिए समय बिलकुल नहीं होता। महिलाएं परिवार की देखभाल करतीहैं। वे अपने जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी रखती हैं, लेकिन खुद की सेहत का नहीं। गौरतलब है कि योग करना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। योगा करने से मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। स्वस्थ मन और फिट शरीर वाली महिलाएं परिवार के स्वास्थ्य को बढ़ाने में संभावना रखती हैं। इसलिए, यह कहना उचित होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य एक स्वस्थ समुदाय की कुंजी है। चलिए आपको ऐसे 4 योगासनों के बारे में जिन्हें जरुर करना चाहिए।

ताड़ासन

महिलाएं खुद को स्वस्थ रखने के लिए ताड़ासन कर सकती है। ताड़ासन मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही, यह पीठ के तनाव को कम करने में मदद करता है। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाते हुए सीधा खड़े हो जाएं। इसके बाद हाथों और एड़ियों को ऊपर उठाते हुए जितना हो सके शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें।

वीरभद्रासन

वीरभद्रासन सबसे अनोखे आसनों में से एक है क्योंकि यह खड़े होने और शरीर को संतुलित करने की दोनों गतिविधियों को जोड़ती है। इस मुद्रा में, एक पैर 90 डिग्री के कोण पर आगे की ओर झुका होता है जबकि दूसरा पिछला पैर 15 डिग्री के कोण पर पीछे की ओर फैला होता है, हाथ हवा में सीधे होते हैं। कम से कम 20 सेकंड तक रुकें और दोहराएं। यह आसन संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और पीठ की मांसपेशियों, हैमस्ट्रिंग और कंधे की मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है।

त्रिकोणासन

त्रिकोणासन का अभ्यास करने से पैरों, रीढ़ की हड्डी और पीठ को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही, इसे करने से डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है।

वृक्षासन

वृक्षासन या वृक्ष मुद्रा, चिंता कम करने के लिए एक शक्तिशाली योगा के रूप में सामने आया है। जैसे ही आप एक पेड़ की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, एक पैर जमीन पर रखते हैं जबकि दूसरा पैर भीतरी जांघ या पिंडली पर रखते हैं, आप स्थिरता और आंतरिक शक्ति की भावना पैदा करते हैं। यह मुद्रा केंद्रित श्वास को प्रोत्साहित करती है, मन और शरीर के बीच संबंध को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही, पैरों और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत मिलती है।

● दिव्यांशी भदौरिया

शरीर की हर नस को एक्टिव करता है लघु वज्रासन, रूटीन में ऐसे करें शामिल

आज के समय में हर कोई अपनी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा बिजी है। इसलिए खुद के लिए समय निकाल पाना काफी मुश्किल है। लेकिन बढ़ती बीमारियों और इंफेक्शन को देखते हुए यह जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। आप रोजाना लिटिल थंडरबोल्ट कर सकते हैं।

इसको करने से न सिर्फ आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि यह आपकी सेहत पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको लघु वज्रासन करने का सही तरीके और फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।

फायदे

- यह आसन हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और एड़ियों को फैलाता है। शरीर के इन हिस्सों के लचीलेपन में सुधार करने में सहायता मिलती है।
- लघु वज्रासन रीढ़ की हड्डी के साथ ही मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। इससे बेहतर पोश्चर मिलने के साथ ही रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ रहती है।
- यह आसन पाचन तंत्र सहित पेट के अन्य हिस्सों को उत्तेजित करने का काम करता है। जिससे पाचन में सुधार होने के साथ ही अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।
- इस आसन में पेट को हल्का दबाने से मल त्याग को बढ़ावा मिलता है। इससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है।
- लघु वज्रासन को रोजाना करने से तनाव और चिंता कम होने के साथ मन शांत होता है और मानसिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
- यह पोश्चन पेट के आसपास ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता। यह ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है दिल के स्वास्थ्य को बेहतर रखता है।
- इस आसान को करने से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याएं भी कम होती हैं।

ऐसे करें लघु वज्रासन

- इसको करने के लिए अपने घुटनों को एक साथ मिलाते हुए फर्श पर घुटने टेककर बैठें।
- फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हिप्स को एड़ियों पर रखें।
- इसके बाद हाथों को जांघों पर रखें और हथेलियों को नीचे रखें।
- अब गहरी सांस लें और रीढ़ को ऊपर की ओर लंबा रखें।
- फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ें और धीरे-धीरे पीछे की तरफ झुकें। अब अपने हिप्स को पीछे रखकर खुद को सहारा दें।
- शरीर को फर्श की ओर नीचे लाएं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी कोहनियों को थोड़ा झुकाएं।
- अब सीने को ऊपर की ओर उठाएं और पीठ के निचले हिस्से से एक आर्च बनाएं।
- गहरी और समान रूप से सांस लेते हुए 15-30 सेकेंड तक इसी पोजिशन में बने रहें।
- इसके बाद धीरे-धीरे सीधे बैठने की स्थिति में वापस आएं और घुटनों पर बैठ जाएं।

कलौंजी को करें डाइट में शामिल, मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी है। इसमें आप कलौंजी को भी शामिल कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कलौंजी में कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रीडिएंट होते हैं जो फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं।

भारत में मसालों के बिना हर व्यंजन अधूरा है। यूं तो हम अपनी किचन में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें से एक कलौंजी भी है। इसे काला जीरा भी कहा जाता है। कलौंजी का उपयोग कई रूपों में किया जाता है जैसे कलौंजी का तेल, भुने हुए बीज, कच्चे बीज आदि।

यह एक ऐसा मसाला है कि यह स्किन की कई समस्याओं से निपटने से लेकर थायरॉयड से लड़ने तक, कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें विटामिन, फाइबर, अमीनो एसिड,

प्रोटीन, फैटी एसिड और कई अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कलौंजी से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदों के बारे में बता रहे हैं-

मेमोरी को करें बूस्ट

कलौंजी के बीज का सेवन करने से आपकी मेमोरी पर अच्छा असर पड़ता है। आप हर दिन कलौंजी के बीज को शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। वहीं, आयुर्वेद में पुदीने की पत्तियों के साथ कलौंजी के बीज खाने की सलाह दी जाती है, जो याददाश्त को बढ़ाने और अल्जाइमर रोग जैसे न्यूरालॉजिकल डिसऑर्डर को रोकने में मदद कर सकते हैं।

वजन कम करने में मददगार

वजन घटाने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी है। इसमें आप कलौंजी को भी शामिल कर सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कलौंजी में कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रीडिएंट होते हैं जो फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें एंटी-ऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट भी होते हैं जो वजन घटाने में भी योगदान दे सकते हैं।

स्किन प्रोब्लम्स को करें मैनेज

कलौंजी या काले बीज का एक फायदा यह है कि इसमें जीवाणुरोधी, रोगाणुरोधी, एंटी-वायरल, एंटीफंगल और एंटी-पैरासिटिक गुण होते हैं जो सोयारसिस, एक्ने और यहां तक कि विटिलिगो के घावों को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए, अगर आप अपनी स्किन प्रोब्लम्स से नेचुरली छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कलौंजी को डाइट का हिस्सा बनाएं।

ब्लड शुगर को करें कंट्रोल

अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कण्ट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कलौंजी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ फ़ार्मास्युटिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अपने आहार में कलौंजी के बीज शामिल करने से आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

● मिताली जैन

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी 18 को किसान सम्मेलन के लिए जा सकते है वाराणसी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को

उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं, सूत्रों ने बताया। रविवार को रिकॉर्ड तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला वाराणसी दौरा हो सकता है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि किसान सम्मेलन के लिए रोहनिया या सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक स्थान का चयन करने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर गुलाब बाग स्थित पार्टी कार्यालय में महानगर और जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के एक दिवसीय दौरे के दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेने की उम्मीद है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटेल ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के वाराणसी में भव्य स्वागत की तैयारी करने को कहा गया है।

विधायक दल के नेता चुने गए चंद्रबाबू, 12 को लेंगे शपथ

अमरावती। एन चंद्रबाबू नायडू को मंगलवार

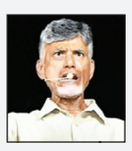

को उनकी तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों के साथ-साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जन सेना के विधायकों द्वारा आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। नायडू ने कहा, बीजेपी, जनसेना और टीडीपी के सभी विधायकों ने मुझे आंध्र प्रदेश की एनडीए सरकार का आगामी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इससे पहले सुबह, नायडू को सर्वसम्मति से टीडीपी विधायक दल का नेता चुना गया। टीडीपी के आधिकारिक समाचार बुलेटिन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के साथ जनसेना और भाजपा के कुछ नेता 12 जून को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नायडू 12 जून को पूर्वाह्न 11.27 बजे गन्नवरम हवाईअड्डे के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

मंत्रालय बंटवारे में बिहार को मिला झुनझुना : तेजस्वी यादव

पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी आशंका जतायी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार की जो सरकार है, वह बैसाखी पर है। वहीं मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारे पर बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को झुनझुना दे दिया गया है। वैसे मेरा मानना है मंत्रालय किसी को भी मिले काम होना चाहिए। तेजस्वी ने एक्स पर प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के नवनियुक्त सदस्यों को शुभकामनाएं भी दीं। तेजस्वी यादव ने जेडीयू, भाजपा और एनडीए सहयोगियों को विभाग आवंटन को 'झुनझुना' बताया है और कहा है कि बिहार के नए मंत्रियों को दिए गए विभाग उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि राज्य की भूमिका है। बेशक, विभागों का बंटवारा करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है।

मानहानि मामले में राहुल को 6 जुलाई को उपस्थित रहने निर्देश

रांची। राहुल गांधी मानहानि मामले में मंगलवार

को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को इससे पहले ही सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता जतायी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतवाद दायर की थी। इसके बाद इस केस को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

विभागों के बंटवारे के बाद नायडू और नीतीश असंतुष्ट : राउत

मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)

नेता संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट हैं। संवाददाताओं से बातचीत में संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राकांपा प्रमुख शरद पवार के लिए इस्तेमाल किये गये शब्द भटकती आत्मा का भी जिक्र किया और कहा कि यह भटकती बेचैन आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि केन्द्र और महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकारों को बेदखल नहीं कर दिया जाता। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को लगता है कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देश के हित में नहीं है तो उन्हें इसे गिरा देना चाहिए।

पहले दिन ही एक्शन में आये मोदी के सारे मंत्री, 100 दिन के कार्य एजेंडे पर काम शुरू

नईदिल्ली। मोदी सरकार के नये मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों में जाकर कामकाज संभाल लिया और प्रधानमंत्री ने 100 दिनों का जो कार्य एजेंडा दिया है उस पर पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया। जिन मंत्रियों की अपने पुराने विभाग में ही वापसी हुई है उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले दिन से मोर्चा संभाल लिया और जिन मंत्रियों को नये विभाग मिले हैं या जो लोग नये मंत्री बने हैं उन्होंने अपने अपने विभाग संभालने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज को समझा और आगे के लिए दिशानिर्देश दिये। विदेश मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने तो पहले ही दिन कई अहम संदेश भी दे दिये हैं। जहां तक नई सरकार के कार्यभार संभालने की बात है तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अपना कामकाज संभाल लिया था। प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी की थी जिसमें कई अहम निर्णयों को मंजूरी दी गयी। सोमवार देर शाम प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया था जिसके बाद आज एक-एक करके मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया।

जयशंकर का बयान

कुछ बड़े नामों का जिक्र करें तो आपको बता दें कि राजनयिक से नेता बने एस. जयशंकर ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। जयशंकर भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें पिछली सरकार में संभाले गए मंत्रालयों की ही जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण सहित कई वरिष्ठ नेताओं को फिर से वही मंत्रालय सौंपा गया है, जो पिछली सरकार में उनके पास था। जयशंकर ने पद संभालने के बाद कहा कि भारत, चीन के साथ सीमा पर शेष मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में काफी तनाव आया है। विदेश मंत्री के रूप में कामकाज संभालने के कुछ ही समय बाद जयशंकर ने पाकिस्तान से होने वाले सीमापार आतंकवाद का जिक्र भी किया और कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयास किये जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि 'भारत प्रथम' और 'वसुधैव कुटुम्बकम' भारतीय विदेश

नीति के दो दिशानिर्देशक सिद्धांत होंगे। चीन के साथ संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि उस देश की सीमा पर कुछ मुद्दे बने हुए हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ''चीन को लेकर हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि बाकी मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए।'' इस्लामाबाद को लेकर नई सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने प्रमुख मुद्दे के रूप में सीमापार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को चिह्नित किया। उन्होंने कहा, ''पाकिस्तान के साथ हमारा आतंकवाद का मुद्दा है - सीमा पार आतंकवाद - हम इसका समाधान कैसे ढूंढ़ सकते हैं... यह एक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती।'' विदेश मंत्री ने सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बारे में भी संक्षिप्त वार्ता की। उन्होंने कहा, ''भविष्य की ओर देखते हुए, मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि प्रधानमंत्री ने हमें जो दो सिद्धांत दिए हैं- भारत प्रथम और वसुधैव कुटुम्बकम - ये भारतीय विदेश नीति के दो मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे।'' उन्होंने कहा, ''हम सभी को पूरा विश्वास है कि यह हमें विश्व बंधु के रूप में स्थापित करेगा- एक ऐसा देश जो बहुत अशांत दुनिया में है, एक बहुत विभाजित दुनिया में है, संघर्षों और तनावों की दुनिया में है। यह वास्तव में हमें एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करेगा जिस पर कई लोगों का विश्वास है, जिसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा, जिसके हितों को आगे बढ़ाया जाएगा।'' जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने पिछली सरकार में अत्यंत अच्छा काम किया है और मंत्रालय में एक बार फिर काम करना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए यह बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मुझे एक बार फिर विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने वास्तव में असाधारण प्रदर्शन किया था।

किरेन रीजिजू ने विपक्ष से कही बड़ी बात

इसके अलावा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा है कि वह संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संख्या बल के आधार पर संसद में एक-दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रीजीजू ने अपने पूर्ववर्ती प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन की मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ''हमें संख्या बल के आधार पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग संसद के बाहर बाहुबल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सदन के अंदर हमें अच्छी बहस करनी चाहिए और मुखरता से अपनी बात रखनी चाहिए।'' रीजीजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की गरिमा बनाए रखने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा, ''मैं यहां सकारात्मक भाव से आया हूं। हम सभी को साथ लेकर चलने और संसद चलाने का पूरा प्रयास करेंगे।

अमित शाह ने संभाला कामकाज

इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता

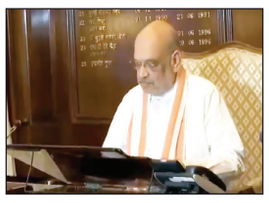

अमित शाह ने भी आज केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कामकाज संभाल लिया। वह 2019 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंत्रालय में प्रभार संभालने से पहले शाह ने चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और देश की सेवा करते हुए जान न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह (59) लोकसभा चुनाव में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। शाह सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। गृह मंत्री के रूप में नए कार्यकाल में, शाह की तत्काल प्राथमिकता तीन नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू कराना होगी। एक जुलाई से लागू होने वाले ये कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के परिदृश्य को नया आकार देने के उद्देश्य से, शाह ने पिछले साल ये तीन कानून पेश किए थे, जिनका उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलना और उन्हें आधुनिक बनाना है।

साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू करने सहित प्रमुख नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाह को उनकी गहरी सूझबूझ के लिए जाना जाता है। उनका कार्यकाल सक्रियता से निर्णय लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, जो भारतीय राजनीति में उनके दीर्घकालिक प्रभाव के उदाहरण हैं। शाह ने माओवादी हिंसा को कम करने और रणनीतिक शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बाद देश में दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाने वाले शाह को उनकी राजनीतिक सूझबूझ और रणनीतिक कौशल के लिए भी जाना जाता है।

नड्डा ने भी संभाला कामकाज

इसके अलावा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाला। भाजपा की पिछली सरकार में मनसुख मंडाविया रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे।

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद सोमवार को नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ-साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी आवंटित किया गया था। नड्डा ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। उसके बाद 2019 में उन्हें भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा गया और जनवरी 2020 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की देखरेख के लिए छह महीने का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। हम आपको बता दें कि नड्डा (63) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वह 1991 में भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने भाजपा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। कई राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। नड्डा वर्ष 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर उन्हें भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था।

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यभार संभाला

इसके अलावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने भी आज केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है।

शिवराज (65) को 'मामा' और 'पांव-पांव वाले भैया' कहकर भी संबोधित किया जाता है। उन्होंने रविवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह उनके तीन दशक से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शासन में उनके व्यापक अनुभव तथा ग्रामीण आबादी के साथ गहरे जुड़ाव के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में चौहान की नियुक्ति से कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में सरकार के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है। चौहान ने मध्य प्रदेश में किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सामाजिक-आर्थिक चिंताओं पर गौर किया और अपने दम पर %धरती पुत्र% की छवि बनाई। भाजपा नेतृत्व ने पिछले साल उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने का फैसला किया था। भाजपा नेता ने विदिशा लोकसभा सीट पर प्रभावशाली जीत दर्ज की और मंत्रिमंडल में शामिल होकर दरकिनार किए जाने के दावों को पर पूर्ण विराम लगाया।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और अमेरिका के बीच मुकाबला आज

न्यूयॉर्क। टी20 वर्ल्डकप 2024 का 25वां

मुकाबला भारत और अमेरिका टीम के बीच 12 जून को खेला जाएगा। ये मुकाबला न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। जैसा की हम सभी जानते हैं कि दोनों टीमों को टी20 विश्व कप 2024 में ग्रुप ए में रखा गया है। बात करें भारतीय टीम की तो, टीम इंडिया ने अभी तक अभियान में दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं अमेरिका ने भी अभी तक अभियान में दो मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। खास बात तो ये है कि दोनों ही टीमों ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। शिवम दुबे गेंद और बल्ले दोनों से ही नाकाम साबित हुए हैं। शिवम दुबे को पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा सके। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा शिवम दुबे से गेंदबाजी कराने का रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे में बड़ी टीमों के खिलाफ शिवम दुबे का प्लेइंग इलेवन में होना भारतीय टीम के लिए सिर दर्द साबित हो सकता है।

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज।

अमेरिका टीम की संभावित प्लेइंग 11

स्टीवन टेलर, मोनंक पटेल (कप्तान और विकेटकीपर), एंड्रीस गौस, आरोन जोन्स, नितीश कुमार, कोरी एंडरसन, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, नोस्तुश केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 33.49 अंक टूटा निफ्टी 23,265 पर बंद हुआ

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार भारी उतार-चढ़ाव भरे वाले कारोबार में मंगलवार को लगभग सपाट बंद हुआ। चुनावी हलचल कम होने नयी सरकार के स्थापित होने के बाद निवेश अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर होने वाले निर्णय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय इस सप्ताह के अंत में मुद्रास्फीति के साथ-साथ ब्याज दरों को लेकर अपना फैसला सुनाएगा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज तेजी के साथ 76,680.90 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 76,860.53 और 76,296.44 अंक के बीच झूलने के बाद अंत में 0.04 प्रतिशत या 33.49 अंक की मामूली गिरावट लेकर 76,456.59 पर बंद हुआ। इसके उलट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.02 प्रतिशत या 5.65 की मामूली सी बढ़त लेकर 23,264.85 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एलएंडटी का शेयर सबसे ज्यादा 1.64 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।

सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड नियमों में दी ढील

नईदिल्ली। बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता नियमों में ढील देते हुए नामांकन का ऑप्शन नहीं देने पर खातों को फ्रीज करने के नियम को समाप्त कर दिया है। सेबी के इस कदम से भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक अब लाभांश, ब्याज या प्रतिभूतियों को आसान से भुना सकेंगे। इसके साथ ही निवेशक 'नामांकन का विकल्प' न चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या आरटीए (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) से किसी भी सेवा पाने के हकदार होंगे। इससे पहले सेबी ने सभी मौजूदा पर्सनल म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी।

मई में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 4 फीसदी बढ़ी : सियाम

नईदिल्ली। देश में यात्री वाहनों की थोक

बिक्री मई में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 3,47,492 इकाई हो गयी। उद्योग संगठन सियाम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मई 2023 में थोक बिक्री कुल 3,34,537 इकाई रही थी। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने एक बयान में कहा, '' यात्री वाहनों में केवल मध्यम वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष का उच्च आधार प्रभाव है।'' मई में दोपहिया वाहनों की बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 16,20,084 इकाई हो गई, जबकि मई 2023 में यह 14,71,550 इकाई थी। पिछले महीने तिपहिया वाहनों की बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 55,763 इकाई हो गई, जबकि मई 2023 में यह 48,610 इकाई थी।

अदाणी ग्रुप ने किया यूएई के ईडीजीई ग्रुप से करार

नईदिल्ली। एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अदाणी की कंपनी अदाणी डिफेंस ऐंड एयरोस्पेस ने अबू धाबी के टेक्नोलॉजी ग्रुप एज ग्रुप (ईडीजीई) के साथ 11 जून को समझौता किया है। अदाणी एंटरप्राइजेज की डिफेंस सेक्टर कंपनी ने बयान जारी करते हुए बताया कि इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर रक्षा और एयरोस्पेस क्षमता के क्षेत्र में एक-दूसरे की मदद करेगीं, ताकि उसका फायदा उठाकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जा सके और एक-दूसरे के प्रोडक्स पोर्टफोलियो को साथ लाया जा सके। कंपनी ने कहा कि इससे ग्लोबल और लोकल लेवल पर कस्टमर्स की जरूरतें पूरी होंगी। सौदे के तहत ईडीजीई ग्रुप और अदाणी ग्रुप के मुख्य उत्पाद क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा।

आर्थिक विकास के दृष्टि से 2023-24 भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

भारत में निजी खपत कुल सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत है। यदि सकल घरेलू उत्पाद के इतने बड़े हिस्से में वृद्धि नहीं होगी अथवा कम वृद्धि दर होगी तो देश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर भी विपरीत रूप से प्रभावित होगी। भारत में निजी खपत इसलिए भी नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू देयताएं सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत के उच्चत्तम स्तर पर पहुंच गईं हैं एवं बचत की दर भी सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत पर अपने निचले स्तर पर आ गई है, जो 10 वर्ष पूर्व 7 प्रतिशत से अधिक थी।

वहीं दूसरी ओर, दिसम्बर 2023 के प्रथम सप्ताह में भारत ने फ्रांस एवं ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए शेयर बाजार के पूंजीकरण के मामले में पूरे विश्व में पांचवा स्थान हासिल कर लिया था। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान एवं हांगकांग थे। परंतु, केवल दो माह से भी कम समय में भारत ने शेयर बाजार के पूंजीकरण के मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण 4.35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का हो गया है। अब ऐसा आभास होने लगा है कि भारत अर्थ के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में नैशनल स्टॉक एक्स्चेंज पर लिस्टेड समस्त कम्पनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का स्तर 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर जुलाई 2017 में पहुंचा था और लगभग 4 वर्ष पश्चात अर्थात मई 2021 में 3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया था तथा केवल लगभग 2.5 वर्ष

पश्चात अर्थात दिसम्बर 2023 में यह 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को भी पार कर गया था और अब यह 4.35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर से भी आगे निकल गया है। इस प्रकार भारत शेयर बाजार पूंजीकरण के मामले में आज पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है।

प्रथम स्थान पर अमेरिकी शेयर बाजार है, जिसका पूंजीकरण 50.86 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। द्वितीय स्थान पर चीन का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 8.44 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। वर्ष 2023 में चीन के शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को ऋणात्मक प्रतिफल दिए हैं। तीसरे स्थान पर जापान का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 6.36 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। चौथे स्थान पर भारत का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 4.35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। पांचवे स्थान पर हांगकांग का शेयर बाजार है जिसका पूंजीकरण 4.29 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जिस तेज गति से भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण आगे बढ़ रहा है, अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय पश्चात ही भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण जापान शेयर बाजार के पूंजीकरण को पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। उक्त सफलताओं के साथ ही, भारत ने अपने आर्थिक विकास की दर को तेज रखते हुए अपने राजकोषीय घाटे पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा 17 लाख 74 हजार करोड़ रुपए का रहा था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 16 लाख 54 हजार करोड़ रुपए का रह गया है। यह राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5.8 प्रतिशत था जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 5.6 प्रतिशत रह गया है। भारत के राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.1 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत तक नीचे लाने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा सफलता पूर्वक किए जा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश भी अपने राजकोषीय घाटे को कम नहीं कर पा रहे हैं परंतु भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यह बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होने पर इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। केंद्र सरकार ने खर्च पर नियंत्रण किया है एवं अपनी आय के साधनों में अधिक वृद्धि की है।

उद्योग मंत्री देवांगन ने ली मैराथन बैठक विभाग की हर एक योजना की समीक्षा की, दिए गए निर्देश

उद्योग विभाग में कसावट लाने की कवायद शुरू

रायपुर। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंगलवार को उद्योग विभाग की एक-एक योजना की विस्तार से समीक्षा की।बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग स्थापना के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर जमीन आबंटन की प्रक्रिया निरस्त करने की कार्रवाई करे। आज मंगलवार को सर्किट हाऊस रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधकों, सीएसआईडीसी के अधिकारियों व उद्योग संचालनालय के उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, संचालक उद्योग पी. अरूण प्रसाद सहित जिलों से आए अधिकारी एवं उद्योग संचालनालय के अधिकारी उपस्थित थे। उद्योग मंत्री देवांगन ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के आदर्श आरचण संहिता के दौरान जो कार्य लंबित थे, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही करें। मंत्री ने औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारीगण समय-समय पर बायलर का निरीक्षण करते रहें। विभाग के योजनाओ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 2023द्ध24 में 1024 लक्ष्य की तुलना में अब तक 1252 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया।मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 600 लक्ष्य की तुलना में 1129 आवेदन स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत अब तक एमएसएमई रायपुर द्वारा अब तक 10798 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस कार्य में मंत्री श्री देवांगन ने तेजी लाने के निर्देश दिए गए।भू आबंटन के 758 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया, 30 पेंडिंग मामलों को भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हॉल ही में तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। वे भी चाहते है कि युवाओं को अधिक से अधिक काम मिले जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की भी मंशा है की अलग अलग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें ताकि रोजगार के अवसर सृजित हों सके। उद्योग मंत्री ने इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस योजना, विभिन्न अनुदान, छुट एवं रियायतों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की और फ्री-होल्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, उद्योंगों के लिए किए गए एम.ओ.यू. की प्रगति, अधोसंरचना विकास कार्य, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कार्यों, वाष्पयंत्र निरीक्षणालय कार्यों, पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाएं की समीक्षा की गई। राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य प्रोत्साहन बोर्ड को सक्रिय भूमिका निभाने और निवेश आकर्षित करने का निर्देश दिया गया । नई सरकार में उद्योग विभाग को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को उद्योग संचालन में आवश्यक सहयोग करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल: एक बुजुर्ग व्यक्ति के कानों में फिर से गूंजेगी आवाज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल की वजह से आज एक 72 वर्षीय व्यक्ति फिर से लोगों की आवाज सुन सकेगा। जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के रहने वाले श्री रामदेव राम कायता को कानों में कुछ समस्या होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। कायता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय आकर मुख्यमंत्री साय के समक्ष अपनी समस्या के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा श्री रामदेव राम कायता के दोनों कानों में डिजिटल श्रवण यंत्र फिट किया गया। इस श्रवण यंत्र के माध्यम से वे आसानी से आवाज को सुन सकेंगे। कायता ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की वजह से आज वह फिर से सुन सकेंगे। उनकी समस्या का इतनी जल्दी निराकरण हो जायगा उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक पंकज वर्मा मौजूद थे। रामदेव राम कायता के कानों में जो डिजिटल श्रवण यंत्र फिट किया गया है। यह आधुनिक डिजिटल यंत्र लगभग 50 हजार मूल्य का है।

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता धरमलाल कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी व पूर्व विधायक रजनीश सिंह, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद ने भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से सौजन्य भेंटकर उन्हें वर्तमान मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर सहृदय बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प व निरंतर प्रयासों से सम्पूर्ण भारत की शिक्षा प्रणाली और सुदृढ़ होगी एवं भारत शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

स्वयंभू प्रकट श्री गणेश मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रनपुर में आयोजित

वित्त मंत्री चौधरी ने पूजा-पाठ कर किया पौधारोपण

रायपुर। जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम रनपुर में श्री गणेश मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए है। उन्होंने नवनिर्मित मंदिर में पूजा-पाठ कर परिसर में पौधा रोपण भी किया। उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। ग्राम रनपुर सहित आसपास के क्षेत्रवासियों के सहयोग से रनपुर में श्री गणेश जी भगवान का भव्य मंदिर निर्माण कराया गया है। इस नव निर्मित मंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया ।जिसमें प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सभा में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। उक्त सभा को मंत्री सहित मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी संबोधित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जशपुर जिले की जनता ने अपने चहेते नेता को आज प्रदेश की बागडोर सौंपा है। प्रदेश मुखिया के रूप में आज आदिवासी नेता और बेटा आपकी सेवा कर रहे हैं। मुझे प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच भेजा है। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है । सभी वर्गों के हितार्थ योजना बना कर धरातल पर उतार रही है। किसान, महिला,युवा सबको सरकार साथ लेकर चल रही है। आने वाले पाँच सालों में जशपुर जिले की विकास के लिए हमारी सरकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम हर दिशा में काम कर रहे हैं।

बाबू भैया की कलम से ✍

गठबंधन की राजनीति बनाम एकाधिकार की सोच

भले ही मजबूरी में साथी दलों के खास करके टीडीपी व जदयू के सहयोग से ही केंद्र में नरेन्द्र मोदी ने सरकार बनाई है। मंत्रिमंडल गठन में साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपनी कोर टीम को बरकरार रखने में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया।अपने प्रमुख साथियों राजनाथ सिंह,अमितशाह,नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन,एस.जयशंकर पीयूष गोयल,धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव को प्रमुख वही विभाग दिए जिनमें वे दूसरे कार्यकाल की सरकार में काबिज थे। कुछ के विभाग में तो और विभाग भी जोड़ दिए। अपने कोर ग्रुप में इजाफा करते हुए,प्रमुख विभागों के साथ शिवराजसिंह चौहान व पुराने विश्वस्त साथी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा तथा मनोहर लाल खट्टर को भी बड़ा विभाग देकर जोड़ लिया। मध्यप्रदेश में लोकप्रियता के चरम पर रहे शिवराज मामा के लिए देश में लाखों की नजर थी कि मुख्यमंत्री ना बनाकर उनके लिए अप्रिय स्थिति पैदा करने वाले अमित शाह व नरेंद्र मोदी की जोड़ी केंद्र में उनके साथ न्याय करेगी या नहीं। जनता की चाह को हाई कमान ने अपमानित नहीं किया। किसान पृष्ठभूमि से जुड़े शिवराज मामा को कृषि के साथ ग्रामीण विकास-किसान कल्याण विभाग दे दिया। बर्षों से न्याय की आस में निरंतर अपमानित हो रहे देश के किसानों से न्याय करने का अहम जिम्मा भी उन्हें सौंप दिया है। अब यह अलग बात है कि पिछले कार्यकाल की अमित-नरेंद्र की जोड़ी ने जिस प्रकार से किसानों से चर्चा के दौरान हस्तक्षेप किया वैसा ही फिर हो तो मामा के लिए भी किसानों को न्याय दिलाना खास कर एमएसपी तय करना कठिन होगा। लेकिन अगर उन्हें फ्री हैंड दिया गया तो निश्चित ही वे इसका कोई ना कोई सकारात्मक हल ढूंढ लेंगें। किसान नेताओं को भी उनकी पोस्टिंग से कुछ उम्मीद जरूर जागी होगी। नए मंत्रिमंडल पर एक नजर डालें तो साफ परिलक्षित होता है कि सारे प्रमुख विभाग भाजपा ने अपने हाथ में रखे हैं। पुराने साथियों सर्वानंद सोनोवाल,प्रल्हाद जोशी,गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया,भूपेंद्र यादव,गजेंद्र सिंह शेखावत,किरेन रिजिजू,हरदीपसिंह पुरी, डॉ. मनसुख मांडविया,राव इंद्रजीत सिंह ,डॉ. जितेंद्र सिंह,अर्जुनलाल मेघवाल , व अन्य अनेक पुराने राज्य मंत्रियों को भी स्थान दिया। तीसरी बार की एनडीए की सरकार में भी नरेन्द्र मोदी की सरकार की छाप बरकरार रखते हुए भाजपा का परचम ऊपर रख कर सहयोगी दलों को संकेत दे दिया है। सरकार भले ही एनडीए की बनी हो लेकिन ताकतवर नरेंद्र मोदी ही रहेंगें। चलेगी भी अमित शाह-नरेंद्र मोदी की ही। दबाव की राजनीति वे चलने नहीं देंगें। ना ही अपने एजेंडे में कोई खास परिवर्तन करेंगें। हालांकि अभी तो यह अनुमान ही लगाया जा रहा है,आगे आगे देखना होगा कैसे कैसे,क्या क्या होता है। सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे साफ होता जाएगा कि गठबंधन की सरकार किस दिशा में जाएगी। नेतृत्व के रंग-ढंग चाल-चरित्र ,बोल-चाल में कितना परिवर्तन आता है। ध्यान सबका उसी पर है। अपने सलाहकार मंडल के बुजुर्ग नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी के साथ अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं देवेगौड़ा, कांग्रेस के मनमोहन सिंह व पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से आशीर्वाद लेकर उन्होंने यह जताने का काम किया है कि वे अब नए अवतार में परिवर्तित होकर काम करेंगे। शायद अब मोदी की सरकार की जगह एनडीए की सरकार ले लेगी ऐसी सबको उम्मीद है।

नई सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं इन चुनौतियों से निपटने सरकार की स्थिरता ना सिर्फ कायम रहे बल्कि दिखनी भी चाहिए। अभी तो टीडीपी सरकार को अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के मुस्लिम समाज से किये गए वायदों का हिसाब भाजपा नेतृत्व के साथ मिलकर देना होगा। इसमें कोई बीच का रास्ता निकलना बहुत मुश्किल है। या तो भाजपा नेतृत्व इसको चुपचाप बरदास्त करे। जो शायद संभव ना हो पायेगा। भाजपा यह भी कह सकती है कि यह राज्य का अपना निजी मामला है। अधिकांश बुद्धिजीवियों का मानना है कि रास्ते तो निकलेंगें। सरकार भी स्थिर रहेगी।इसका जनता व भाजपा के समर्थकों पर क्या व कैसा असर होता है। यह भी देखा जाना होगा। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाना चाहेगा। उसका क्या हल निकाला जाएगा। यह देखने की बात होगी। बिहार भी बहुत सी बातों पर अडिग है। जातिगत जनगणना की उसने घोषणा ही कर दी है,कैसे होगी। फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग बिहार की भी है। विभाग वितरण से टीडीपी व जेडीयू खुश हैं या नहीं यह अभी बाहर नहीं आया है। ऊपरी तौर पर लगता तो ऐसा ही है कि सब ठीक है। विभागों का वितरण निश्चित रूप से प्रधानमन्त्री का अपना विशेषाधिकार है। गठबंधन की राजनीति का लेकिन अपना कर्तव्य होता है कि एक दूसरे से सहमति के साथ निर्णय हों। किसी प्रकार की शंका-कुशंका न रहे। सरकार बंधन में रहे यह भी सहयोगी चाहते हैं। लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी अपनी फितरत बदल कर बंधन में रहना पसंद करेंगें। अब तक एकतरफा एम की छत्रछाया में चलती आ रही राजनीति अचानक दो एन पर केंद्रित हो गई है। इस बंधन को तोड़ कर भाजपा अपना कार्यकाल बिना दबाव महसूस किये ,अपने हिदुत्व के एजेंडे के साथ कैसे पूरा करती है। इस पर पूरे भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व की नजर है। देखे क्या होता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

बलौदाबाजार हिंसा मामला: दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा

रायपुर। बलौदाबाजार में प्रदर्शनकारियों ने एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और जमकर बवाल मचाया. इस उपद्रव और हिंसा मामले में सीएम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है. वहीं प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले पर कहा कि छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है. यहां इस प्रकार की घटना का इतिहास नहीं रहा है. ये परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की धरती है. समाज को बदनाम करने वाले असामाजिक तत्वों ने यह षड्यंत्र किया है, इस घटना में जिन लोगों का हाथ है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रात को ही उच्चस्तरीय बैठक ली और मामले की विस्तृत समीक्षा की है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन मुस्तैदी से जांच कर रहा है. सीएम ने समाज प्रमुखों से भी बातचीत की है.

आयुर्वेद महावि. चिकित्सालय में 1802 बच्चों का स्वर्णप्राशन

रायपुर। बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति वर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में सोमवार को 1802 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक सुश्री इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन समन्वयक डॉ. लवकेश चन्द्रवंशी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह काफी लाभदायक है। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा इस वर्ष की अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 25 जनवरी को 1235, 21 फरवरी को 1420, 18 मार्च को 1720, 16 अप्रैल को 1410 और 13 मई को 1256 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया था।

कांग्रेस की हार के लिए जो-जो नेता जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही कब तय होगी?

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रंजना साहू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के ताजा बयान का हवाला देकर उनसे जानना चाहा है कि कांग्रेस की हार के लिए अगर कोई एक नेता जिम्मेदार नहीं है तो जो-जो नेता जिम्मेदार हैं, उनकी जवाबदेही कब तक तय की जा रही है? श्रीमती साहू ने कहा कि कांग्रेस छह माह पहले विधानसभा और अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में हुई अपनी शर्मनाक एक बार फिर अंतर्कलह से घिर गई है और बजाय हार के कारणों की समीक्षा करने के या हार की बौखलाहट में ऊलजलूल व अमर्यादित बयान देकर प्रलाप कर रहे हैं, या फिर आपसे में ही आरोप-प्रत्यारोप करके हार के लिए के एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती साहू ने कहा कि कांग्रेस में एक तरफ लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के नेता हार की समीक्षा की मांग उठाने लगे हैं। चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर अन्य मामलों में पहले भी नाराजगी सामने आई थी। हार के बाद अब वरिष्ठ नेताओं ने कई लोकसभा में बाहर से प्रत्याशी उतारे जाने और स्थानीय लोगों को दरकिनार करने का मुद्दा बना लिया है।

बालश्रम की रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी- साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बच्चे देश का सुनहरे भविष्य एवं समाज की अमूल्य निधि हैं, जिनका सरंक्षण और संवर्धन हम सबकी ज़िम्मेदारी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं का आधार बच्चों को बालश्रम के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों की उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर पर बच्चों का भी समान अधिकार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में न लगाएं, न ही किसी को लगाने दें।

बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी- श्रीमती राजवाड़े- महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कहा है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर ना लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बाल श्रम, बाल तस्करी के कई मामले आज भी सामने आते रहते हैं। लोग कल-कारखानों सहित अपने घर-दुकानों में भी छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाने लगे हैं। इस दौरान बच्चों से दुर्व्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं।

पानी की समस्या, वार्ड पार्षद मृत्युंजय ने दिया धरना

रायपुर। सुन्दर नगर वार्ड में पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद मृत्युंजय दुबे ने वार्डवासियों के साथ मंगलवार की सुबह 11 बजे लाखेनगर ढाल (छप्पन भोग भण्डार के पास) धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 2 बजे जोन 5 आयुक्त विमल शर्मा वार्ड पार्षद मृत्युंजय दुबे के साथ चर्चा करने पहुँचे और कहा कि शाम को आपके वार्ड में पानी आ जाएगा आप धरना समाप्त कर दीजिए। इस पर पार्षद ने कहा कि पिछले 3 महीने से इस क्षेत्र में पानी नही आ रहा है, कई बार सम्बंधित अधिकारियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया लेकिन लगभग 200 परिवारों को अब भी पीने का पानी नही मिल रहा है और अब आप कह रहे हैं कि शाम को पानी आ जाएगा तो शाम 7 बजे तक धरने पर बैठते हैं जब इस क्षेत्र में पानी आएगा तब ही उठेंगे ,यदि शाम को पानी नही आया तो रात में भी यह धरना जारी रहेगा और हम बैठेंगे। पार्षद मृत्युंजय दुबे ने नगर निगम आयुक्त अभिनेष मिश्रा को फोनकर बताया कि जब तक इस क्षेत्र में पानी नही आएगा वह साथियों के साथ धरने पर रहेंगे , यदि शाम को पानी नही आया तो रात में भी यह धरना

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने विशेष सचिव की अगुवाई में बनेगी कमेटी

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा मेडिकल कालेजों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की और उनके मानदेय को बढ़ाने तथा उन्हें नियमित करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग को एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव नोडल अधिकारी होंगे। कमेटी में वित्त तथा स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी के साथ ही किसी मेडिकल कालेज के डीन तथा सीनियर प्रोफेसर भी शामिल होंगे। ये कमेटी एक महीने में विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय और उनके नियमितिकरण करने के प्रावधान के बारे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के प्रावधानों और नियमों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बैठक में राजनांदगांव व कवर्धा समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों की सुविधाओं व स्थापना को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग को लधु एवं दीर्घ लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से काम हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्त पदों को जल्द पीएससी के माध्यम से शीघ्र भर्ती करने की बात स्वास्थ्य मंत्री से कही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक में प्रदेश के निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी शीघ्र स्थापना के लिए आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि जारी कर नेक इरादों की झलक दिखाई

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठित केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी करने और गरीब परिवारों के लिए तीन करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने के व्यक्त संकल्प के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री शर्मा ने कार्यभार सम्हालते ही प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा सर्वप्रथम किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए फाइल हस्ताक्षरित करने से किसानों और गरीब कल्याण के प्रति भाजपानीत राजग सरकार के नेक इरादों की झलक मिल गई है और देश के किसानों में एक बार फिर यह पक्का भरोसा कायम हुआ है कि नई केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम गढ़ेगी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास का नया लक्ष्य घोषित करके श्री मोदी ने नई केंद्र सरकार के गरीब कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 20 हजार करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.